| | | |
|---|---|---|
| 31 | Chandigarh | 0 |
| 32 | Puducherry | 2,470.00 |
| | **Total** | 37,72,884.40 |

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Sir, how is the Government promoting the integration of organic fertilisers with the traditional and modern agricultural practices in Andhra Pradesh? Are there any pilot projects or partnerships with the local farmers to demonstrate the benefits and practical application of organic fertilisers?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

*[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link* https://sansad.in/rs/debates/officials *]*

---

1.00 **P.M.**

## †GENERAL DISCUSSION

## #The Union Budget, 2024-25;
## &
## #The Budget of Union Territory of Jammu and Kashmir, 2024-25

MR. CHAIRMAN: Now, further discussion on the Union Budget, 2024-25 and the Budget of Union Territory of Jammu and Kashmir, 2024-25. I now call upon Members whose names have been received for participation in the discussion; Shri Praful Patel.

**श्री प्रफुल्ल पटेल** (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्हें भी लगातार सातवाँ बजट पेश करने के लिए और अपने आप में एक रिकॉर्ड निर्माण करने के लिए भी बधाई देता हूँ। Sir, I think, we build too much of expectations that something earth-shattering is going to happen in the Budget. But, I must compliment Modi*ji* right from 2014 till today; he has maintained remarkably the fiscal discipline and financial health of the country, over and above all the other happenings in the country. Sometimes,

† Discussion continued from 29.07.2024.

# Discussed together.

you can fall into inducements and you can say that I would like to do this or that for the people. Yes, of course; but there has been continuous progress on every front while maintaining total fiscal discipline and that is the hallmark of this year's Budget also.

Sir, the biggest focus in this year's Budget, as we all know has been on creation of jobs, giving our youth opportunities to employ themselves to be able to make a living and standing on their own feet. A skilling programme has been undertaken in that direction and is well received by the people and the young Indians. That should be the focus not only now but for all the years to come.

In Maharashtra, the Budget of the State Government was announced very recently where when 12th standard students pass out, they are given a monthly stipend of Rs. 6000. A student who passes his diploma gets a monthly stipend of Rs. 8000 and a graduate, before he finds a job for skilling himself gets a monthly stipend of Rs. 10,000. So, if you look at the direction, what has been envisaged in this year's budget of the Union Government as well as what has been delivered in the budget of Maharashtra Government, there is a big parallel to try to skill young Indians to be able to stand on their own feet and make a good living for themselves. We should also pride ourselves in the fact that today because of the huge skill sets, we have engineers, doctors, nurses, scientists, teachers all over the world. If you see we are actually, in a way, sending our skilled manpower who may not have found much employment opportunities here, but towards the other parts of the world, today in Australia, U.K., New Zealand, Canada, United States, you name any country, European countries, even Asian countries. I believe even Japan is encouraging skilled Indians to come and work in their country because of their ageing workforce. Therefore, the skilling programme should be encouraged and that export of skilled manpower should be there. I would say and Mr. Puri will know that in the world we are having the highest inflow of foreign remittances of 110 billion dollars as compared to any other country, including China; it is twice that of China. The reason is: Our skilled people are able to get employment all over the world. After all, हमारे नागरिक हैं, चाहे वे हमारे देश में या कहीं भी मिलें, अपने पैरों में खड़े रहने की उनकी क्षमता बनती है, तो उसका हम लोगों को स्वागत करना चाहिए।

**श्री सभापतिः** आपने यहां बहुत सही कहा, Mr. Puri knows. He has traversed the entire globe.

SHRI PRAFUL PATEL: Right from Brazil to United States and all.

MR. CHAIRMAN: All places.

SHRI PRAFUL PATEL: Now, as Minister, he also has more responsibilities.

MR. CHAIRMAN: Impactful.

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, I would like to state that push for infrastructure sector is also very commendable. If you see Modiji's 2014 Budget till today and the kind of emphasis laid on infrastructure, it is remarkable. आज आप पूरे देश में कहीं भी जाते हैं, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा हुआ है, इसी तरह से हवाई अड्डे और सी पोर्ट्स भी बढ़े हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी का विषय भी है। अभी renewable energy की बात हो रही थी। हमारा renewable energy programme can be considered as one of the most ambitious and most successful renewable energy programmes in the world. सर, इतने बड़े पैमाने पर हम renewable energy पर emphasis दे रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

MR. CHAIRMAN: And, we are one-sixth of humanity!

SHRI PRAFUL PATEL: Yes. We are one-sixth of humanity. We started with hydropower, wind power, solar power, Green power, etc., is all being translated into very efficient and effective forms of alternative renewable energies being produced in our country.

**श्री सभापति**: आपके कहने का मतलब है कि हम किसी भी चक्रव्यूह में नहीं फंसे हैं।

**श्री प्रफुल्ल पटेल**: सर, किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसे हैं।

**श्री सभापति**: मतलब चक्रव्यूह ही बात है, उस पर कोई आधार नहीं है।

**श्री प्रफुल्ल पटेल**: सर, कोई आधार नहीं है। चक्रव्यूह में क्या हो गया है कि यहां के यशस्वी काम की वजह से वे चक्रव्यूह में फंस गए हैं और इसलिए उस चक्रव्यूह को दूसरी तरफ से बताने की कोशिश की जाती है। सर, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर 140 करोड़ के मुल्क में कोई कहे कि हम हर व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का भला रातों-रात कर देंगे, तो यह कभी संभव नहीं है। ...(**व्यवधान**)... जो लोग टीका करते हैं, उन लोगों ने अपने कार्यकाल में हमारे देश के विकास के लिए कितना कुछ उपलब्ध कराकर दिया, यह उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। यह टीका-टिप्पणी करना और टोका-टोकी करना बहुत आसान है। हमने तो उधर बैठने के बाद भी देखा कि मोदी जी ने अपने कई भाषणों में कहा है कि आज देश यहां तक पहुंचा है, उसमें केवल हमारा ही योगदान नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का, जो हमारी सभी सरकारें रहीं, जो प्रधान मंत्री रहे, सबका

योगदान रहा है। तो एक बड़प्पन के साथ जब हमारे ...(**व्यवधान**)... जब हम वहां बैठे थे, तब ये हमारे द्वारा सुनी हुई बातें हैं। इन सब बातों का बहुत महत्व है। यह हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए।

सर, मैं ज्यादा वक्त इसलिए भी नहीं लूंगा, क्योंकि वक्त मर्यादित होता है। फिर भी इधर का वक्त मुझे थोड़ा प्राप्त है, इसलिए I am indulging a little bit. सर, 2004 से 2014 तक मैं भी भारत सरकार में काम कर रहा था। मुझे मालूम है कि उन 10 सालों के दौर में मैनुफैक्चरिंग की मात्रा कम हो गई थी। मतलब मैनुफैक्चरिंग में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, वह नहीं हो रही थी। 2014 से बाद आज तक का जो यह 10 साल का दौर है, इसमें we should be proud that manufacturing in India has revived and revived at a great pace. यह बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात में आपको कह रहा हूं कि हम कितनी भी बातें करें, हम नौकरी की बात करें, unemployment की बात करें, गरीबी की बात करें, किसी भी चीज़ का एक मात्र solution है - जब तक हम देश की अर्थव्यवस्था, economic activity और manufacturing activity को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम अपने देश के मूल प्रश्नों पर सुधार नहीं कर पाएंगे। हमारी सरकार की ख्याति भी है और बजट में भी इस ओर बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। अभी मिलिंद मुरली देवड़ा जी ने यहाँ पर urban development के बारे में बताते हुए cities में rooftop solar panel की बात कही। सर, आज किसी भी शहर में, मध्यम जनसंख्या के शहर में भी जाइए, तो कितनी सारी अलग-अलग स्कीम्स के माध्यम से भारत सरकार की ओर से पैसा दिया जा रहा है। सर, लोगों को तो केवल ऊपर की बिल्डिंग दिखती है, ये Urban Development Minister रहे थे, इनको मालूम है कि आज हमारे शहरों को केंद्र से underground drainage schemes के लिए, water supply schemes के लिए कितना सारा पैसा मिलता है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों को इसका मायना नहीं रहता है, कोई अंदाज नहीं रहता है कि उसके बारे में कितनी सारी चीजें हुई हैं। आज अगर हम लोग एक पूरा चित्र देखें, तो मैं जो renewable energy की बात कर रहा था, आप total energy देखिए। अभी मैं बीच में देख रहा था कि छोटे-छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए भी हमारी भारत सरकार की ओर से पहल हो रही है। France gets more than 75-80 per cent of its electricity generation only from nuclear sources. Europe is moving in that direction. Nuclear energy is, now, a much safer and secure medium of energy. वे जमाने गए कि किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, चेर्नोबिल हो गया, बाकी बहुत जगह ऐसा हुआ। The new technologies are very, very advanced and we should take advantage. India, which has a huge population, huge geography, will need more and more of energy security, as we go by. And, I think, the Government has done immense work at every level to ensure energy security of our country.

सर, अभी Research and Development की भी बात हुई, यह HIV के प्रश्न से चल रही थी। मैं कह रहा हूँ कि आज Research and Development में हमारी फार्मा कंपनीज़, हमारी इंजीनियरिंग कंपनीज़, हमारी डिफेंस कंपनीज़ बड़ी मात्रा में R&D पर, innovation पर ध्यान दे रही हैं और कितने patents मिले हैं! These are developments which don't get talked about. हम लोग छोटी-छोटी बातों में, ऐसा नहीं है कि वे बातें जरूरी नहीं हैं, पर उन बातों में हम लोग ज्यादा उलझ जाते हैं और बहुत सारी जो अच्छी बातें होती हैं, काम होते हैं, उनको हम

नजरअंदाज करते हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है कि यह तो सहज बात है। सर, यह सहज नहीं है। इस देश के भविष्य के लिए और 2047 के विकसित भारत की हम जो बात कर रहे हैं, उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि हम इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और इस पर ध्यान दें।

सर, मैं दो-चार मिनट में खत्म करता हूँ। अभी यहाँ पर taxation की बात हुई। मेरा भी एक निवेदन जरूर है। आज, no doubt, 3 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ है, उसके बाद 3 लाख से 7 लाख, 7 लाख से 10 लाख और उसके आगे अलग-अलग है। इसमें हमें थोड़ा मध्यम वर्ग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 3 लाख रुपए, even with the exemptions, यह बहुत कम मात्रा होती है। आज आप देखते होंगे कि दिल्ली जैसे शहर में अगर किसी को 30-40 हजार रुपए महीने के मिलते हैं और अगर उसको 5 परसेंट टैक्स भरने की भी नौबत आती है, तो यह उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या का सवाल है। मैं मान सकता हूँ कि सरकार की मंशा है कि tax net widen होना चाहिए, मगर दूसरी ओर अब GST के आने की वजह से tax net ऐसे भी बढ़ गया है। Now nobody in the country can say that he is not paying tax. Directly or indirectly, he will end up paying tax.There should be a little more concession to the middle class people to be able to make two ends meet in cities. And, why only in cities? The cost of living and his aspirations should be met in some way or the other.

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

सर, एक last point है। दूसरी बात ऐसी है कि आज हम stock markets की बात करते हैं। Stock markets have become a very effective means of investment for all kinds of individuals, not only the rich, but even for the middle class and even for the people who now have started looking at the stock market to make a little extra money. Fixed deposits and fixed income plans do not get them that kind of return. But, also, there has to be some caution. The caution part is that when stock markets are volatile. After all, market mechanisms work. उसमें किसी सरकार या किसी और के माध्यम से कोई नियंत्रण नहीं होता है, वे market forces होती हैं। इसलिए खास करके जो F&O Section (Future and Options) है, इसमें कहीं न कहीं बजट में थोड़ा-बहुत नियंत्रण लाने की कोशिश की गई है। उसको थोड़ा और भी मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि Future and Options में कम margin में virtually no margin में you are investing and you are playing for future gains. If you end up with future losses, उसका बहुत विपरीत परिणाम, खास करके छोटे निवेशकों पर होता है। इसलिए इस मामले में कहीं न कहीं हम लोगों को थोड़ा-बहुत ध्यान देना होगा।

मैं आखिर में महाराष्ट्र के बारे में एक-दो बातें इसलिए कहूँगा, क्योंकि यह Council of States है। अपने-अपने राज्यों के थोड़े-बहुत विषय यहाँ रखने की सबको जरूरत भी होती है। आखिर हम ही अपने राज्य के विषय को नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा? अन्य राज्यों के विषय रखने और देश के विषय रखने के साथ-साथ हम अपने राज्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर, बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारी इधर-उधर की बातें हुईं। ठीक है, राजनीति में ऐसा होता है,

इधर की बात, उधर की बात, सब अलग-अलग बातें होती हैं। मैं इतना कहूँगा कि महाराष्ट्र के मामले में इस बजट में कोई बोले कि क्या है, क्या नहीं है, तो पहले fine print देखें।

दूसरी बात, अभी कुछ महीने पहले वहाँ पर प्रधान मंत्री जी के हाथों से 76,000 करोड़ के एक पोर्ट का भूमिपूजन हुआ। Western Coast में यह इतना बड़ा पोर्ट बनने वाला है कि देश में आज तक जितने पोर्ट्स हैं, उनसे कहीं बेहतर और बड़ा बनने वाला है। केवल उतना ही नहीं, उसका ecosystem जो बनेगा और उसकी वजह से वहाँ पर जो peripheral infrastructure बनेगा, वहाँ इंडस्ट्रीज आएँगी, मैं आपको एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उससे वहाँ पर 10 लाख से ज्यादा रोजगार, directly or indirectly, उपलब्ध होंगे। अगर किसी राज्य को या किसी भी राज्य को कुछ मिला है, जैसे - आंध्र प्रदेश को बिहार को मिला है, तो मैं कहूँगा कि एज ए भारतीय हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। जब हम सत्ता में थे, तो पार्लियामेंट में Andhra Reorganization Act पास हुआ। मैं लोक सभा में खुद उसका साक्षी रहा हूँ, वह यहाँ से भी पास हुआ। Andhra Reorganization Act उसी वजह से पास किया गया, क्योंकि एक राज्य जब दूसरे राज्य से अलग हुआ, तो जहाँ पर resources थे - वही हाल बिहार का था, जब बिहार और झारखंड अलग हुए। वहाँ की जो परिस्थितियाँ थीं, उनके बारे में तो आपको मुझसे भी बेहतर मालूम है। अगर उन राज्यों के साथ इतने सालों तक किसी ने इंसाफ नहीं किया और अगर आज नरेन्द्र मोदी जी इंसाफ करने के लिए बैठे हैं, तो उसके लिए किसी के पेट में दर्द होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो इसका स्वागत करना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि उसके बनिस्पत कहीं ज्यादा, हजारों करोड़ रुपये का निवेश आ रहा है, भारत सरकार की मदद से महाराष्ट्र में पैसा आ रहा है, already projects बन रहे हैं, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए।

दूसरा, हमारे एक साथी ने मुझे स्मरण कराया कि हमारे महाराष्ट्र में गोंदिया और गढ़चिरौली, दो नक्सल प्रभावित जिले हैं। सर, मैं गोंदिया से हूँ और गढ़चिरौली उसके बगल में है। आज उस नक्सल प्रभावित जिले में iron ore की mining, जिस तरह से बस्तर और गढ़चिरौली का वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और नक्सलवाद की वजह से विकास नहीं हुआ, आज मैं आपको दावे के साथ कहने के लिए खड़ा हूँ कि ऐसा नहीं है कि यह कोई होने वाली बात है, बल्कि वहाँ iron ore की mining आज बहुत बड़े व्यापक तौर पर हो रही है। Finest iron ore in the country is available in Gadchiroli. वहाँ पर उसकी mining शुरू हो चुकी है। वहाँ पर हजारों करोड़ के स्टील के प्लांट्स के निर्माण होने की शुरूआत हो चुकी है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.

**श्री प्रफुल्ल पटेल**: आगे आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र में, खास कर गढ़चिरौली और जो पिछड़ा एरिया है, आदिवासी एरिया है, वहाँ पर हमारे देश की सबसे ज्यादा steel manufacturing होने जा रही है। तो ये सारी बातें हैं। कहीं न कहीं हर तरह से सिर्फ एक दिशा भूल करना -

अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि पिछले 10 सालों में सभी को न्याय, इंसाफ देने की हर बजट में जैसी कोशिश हुई, इस बजट में भी उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। इस बजट का हम सबको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, आप अपने-अपने सुझाव रखिए। आपको और क्या चाहिए, उसके लिए जरूर बात कीजिए, लेकिन केवल विरोध के लिए इसका विरोध करना उचित नहीं है।

मैं इस बजट का स्वागत कहता हूँ। मैं आप सब से भी कहूँगा कि आप इसका थोड़ा और अध्ययन कीजिए तथा आपके पास और अच्छे सुझाव हों, तो जरूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपसभापति :** धन्यवाद, माननीय प्रफुल्ल पटेल जी। माननीय श्री भुबनेश्वर कालिता जी। You have fifteen minutes. ...*(Interruptions)*... कृपया बैठ कर न बोलें।...(**व्यवधान**)... Please. You expect that nobody should interfere in your speech. So, please do follow. Please.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Thank you, hon. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I rise to support the hon. Narendra Modiji-led 3.0 Central Government Budget which has been very ably brought by our Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman. We may mention here that this is her Seventh Budget which is basically a development-oriented and progressive Budget aiming at '*Sabka Sath*, *Sabka Vikas*.' Sir, we all know the goal of this Budget and also what will be the goal of subsequent Budgets. It would be to make India '*Viksit Bharat*.' While going to make India *'Vikhit Bharat'*, it cannot be the economy only although India is the fifth largest economy today and aiming at third largest economy by 2027. When we will complete the hundred years of freedom in 2047, we will become developed India. Sir, while making this county a '*Viksit Bharat*', we have to look into all the sectors, all the sections of the society and all those who live in this country to see that they are *viksit* or they are also developed in all manners. While talking about all sectors, this Budget has covered a number of things and has aimed at all sectors, not only the economy but also the communication, transport, rural development to mention a few.

I would like to mention that the main thrust of the Budget is aimed at five major things, namely, *Gareeb*, *Yuva*, *Annadata*, *Nari*, middle class, and, of course, the infrastructure development. Sir, while speaking about '*Gareeb'*, we have seen, in recent past and also in this Budget, that there are schemes which are aimed at poverty alleviation and making the poorer sections into a real living society of this country. Sir, as we already know that 25 crore people have been brought above the poverty line, and this has been a targetted approach. We have succeeded in that and the Budget has spoken about that. Nearly, 80 crore people are given free food grains so that their living can meet both ends, and this is a sizeable poorer section of our country. We have achieved it and it is aimed to continue this scheme for next five years also. ...*(Interruptions)*... Sir, while talking about ... ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*... You are not allowed. No. Nothing is going on record. Please do not intervene. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: You concentrate on West Bengal. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, please. ...*(Interruptions)*... Speak, Mr. Kalita. ...*(Interruptions)*... कृपया बैठ कर बीच में न बोलें।...(**व्यवधान**)... Please.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, I have already spoken about the *PM Garib Kalyan Yojana* and about how 25 crore people have been brought above the poverty line. Today, with this Budget, Rs. 34 lakh crore have already been disbursed by DBT through the *PM Jan Dhan* accounts under the *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana*. This has minimized and totally finished the role of the middlemen who used to grab this money earlier. So, by sending all this money to the poor sections of society by DBT to the poor farmers, the middlemen culture has vanished from the society, which is reflected everywhere today. Sir, 78 lakh street vendors have benefited as they have been provided credit assistance under the *PM Swanidhi Yojana*. Talking about the *garib*, 2.3 lakh vendors received credit for the third time; 62.36 lakh urban street vendors received Rs. 11,000 crore as collateral-free loans. This has empowered street vendors to formalize their business and has given them access to working capital. These were the sections of people who were neglected earlier. We talk much about *garibi hatao*, but there was no concrete proposal or policy to alleviate or eradicate poverty earlier. But with Shri Narendra Modiji's Government in place, there is a concrete policy to eradicate poverty from the society. This has been done practically and each one of us knows about it.

Sir, the *PM Janman Yojana* aims at reaching particularly vulnerable tribal groups. For that, Rs. 265 crore have been allocated. Another very important sector, as I mentioned earlier, is artisans and craftsmen who are living in rural areas and contributing to the economy. Although they are contributing in a small way, they are contributing in a very significant way. For that Rs. 4,824 crore have been allocated and I am thankful to the hon. Finance Minister for that. Sir, another thing that has been very successfully implemented by many States is the PMAY. Rs. 84,670 crore have been allocated towards that and, in the Pradhan Mantri Awas Yojana, coming year, three crore houses would be added under the PMAY.

Sir, we all know about the *Jal Jeevan Mission*. Every Government talks about providing potable drinking water to all the citizens of this country, but nothing concrete was done earlier till the *Jal Jeevan Mission* came, which aims at providing piped drinking water to each and every family. It would also help provide for better

healthcare because we all know that water is very important for health and people suffer from various diseases because of contaminated water. In Swachh Bharat Yojana, Rs. 12,190 crore has been allocated so that this can be boosted. Swachh Bharat was very effective during Covid pandemic when people followed swachh bharat and achieved good health. PM Shram Yogi Maan-dhan Yojana is for pension of Rs. 3,000 per month after the age of 60, which is a very laudable step, and nearly 50 lakh workers have been enrolled till 31st December, 2023. They will be benefited by PM Shram Yogi Maan-dhan Yojana. Many times Atal Pension Yojana has been mentioned which is effective and implemented in the States and 6.2 crore subscribers, till 17th January, 2024, have been benefited and allocation of Rs.520 crore has been made. We are very thankful to the Modi Government for doing so. Many times in this House, we talk about unemployment and unemployment among the young, which is a very right issue. But what has been done earlier so that the unemployed could get employment? What has been done earlier to make them employment-worthy? In this Budget, three schemes for employment-linked incentives have been announced which will reduce our unemployment problem to a great extent. While going through the Budgetary provisions made in this Budget under Start-up India, tax benefits for certain segments of Start-ups have been extended to 31.03.2025. Above that, a corpus of Rs.1 lakh crore with 50-year interest-free period will be established for the youth. These are the work by which we can eradicate unemployment. It is a continuous problem and it will continue. We may not be able to do away with it altogether, but we can reduce unemployment by giving proper employment to our younger generation. There are many other schemes like PM Mudra Yojana, PMMSY, Atmanirbhar Oilseeds Abhiyan, etc. These are all aimed at making employment as well as generating income for the poorer sections of people. These are certain things that I wanted to mention like eradication of poverty, employment for the younger section of people and welfare of *Annadaata*, our *kisan*, our farmers. Sir, the stress of this Budget, the main importance that this Government is to giving, is to strengthen the *Naari Shakti*, and to make them capable. As they are 50 per cent of the population, the human resource from the woman section has to be harnessed properly so that they can play effective role in nation building. *(Time-bell rings.)*

Sir, I have to mention two things about my State, Assam.This morning also, the issue of flood in Kerala was mentioned and that took about an hour in this House. And, one Member from the CPI(M) Party -- I think he is not present now -- kind of objected mentioning about Assam flood and mitigation of its effects. Sir, 98 people have died in floods. More than seven lakh people are affected. The floods have

inundated the entire State. But, we have not made any noise about giving us package. The State is doing on its own. How can we make Assam a flood-free State? The Government has taken many steps, including steps for conservation of water bodies. As you all know, in my State, and in other State also, water bodies are being encroached for different purposes. As a result, the water bodies are decreasing. So, where will the rainwater go? Either it will flood the habitation or it will go to the water bodies. So, with harnessing of rainwater, we must harness our water bodies also so that these water bodies can absorb the rainwater and floods can be reduced.

As we all know Brahmaputra and its tributaries are the cause of flood in Assam and the North-East. So, our hon. Transport Minister, Shri Nitin Gadkari, once announced that on both the banks of Brahmaputra, north and south banks, the highways would be constructed which would prevent flood water from spreading to habitation and fields. *(Time-bell rings.)* Sir, I will take only two minutes more. The dredging of Brahmaputra and other rivers is very necessary because due to siltation, the level of river beds has come up. So, where will the excess water go? Naturally, it will go to the habitation and the fields, which will create havoc for us. So, the dredging of Brahmaputra and its tributaries was thought of as early as 1972, but, up till now, that has not been implemented properly. I congratulate the Government that they are taking up dredging issue very effectively.

My speech cannot be complete without mentioning about some of the issues related to the Railways because now the Budget also includes the Railways. I must also mention about the transport infrastructure. As I mentioned earlier, infrastructure is one of the main ingredients of this Budget. While talking about transport infrastructure, I would like to highlight that India now has 149 airports, which is twice the number of airports before 2014. Rs. 352.20 crore has been allocated for *Jal Marg Vikas Project* (JMVP) for 2024-25. As you know, waterways are as important as airways and roadways. Sir, 40,000 rail bogies are to be upgraded to *Vande Bharat* standards for safer and more convenient travel for middle-class Indian people. *(Time-bell rings.)* Sir, I want to make only one or two more points. Rs. 6,500 crore have been provided for railway electrification in 2024-25. Ninety-five per cent broad gauge lines are electrified, and, Sir, my State, my region, North-Eastern Region, is one of the beneficiaries. We are having the electrified railway tracks. *(Time-bell rings.)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: For doubling, third line and bypass line works, an outlay of Rs. 2,905.91 crore has been allocated. Three major railway corridors are proposed under *PM Gati Shakti* to improve the logistics efficiency.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. *(Time-bell rings)* आपकी पार्टी से ही समय जाएगा।

SHRI BHUBANESWAR KALITA: My party has got the time. Sir, this Budget has given more importance on the infrastructure and these are some of the infrastructure projects. I also have to mention about the Amrit Bharat stations. One hundred Amrit Bharat stations are already in progress. My own State's railway stations are one of these stations. I congratulate the Finance Minister, the Railway Minister and above all, the hon. Prime Minister for this progressive and development-oriented Budget. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Hon. Members, before I invite Anthiyur P. Selvarasu, hon. ex-Prime Minister, Shri H.D. Devegowda wants to say something. Sir, please be brief. The next speaker is here.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Sir, while my colleague was speaking, I was watching him very closely. I visited Brahmaputra -- this side, where some of the damages had taken place -- during my period. Sir, it is a wide-spread river. It starts from the Himalayas, goes on spreading. Several villages have been washed out. I have gone there. I have constructed retaining walls. I relocated the villagers, who were suffering very badly. I relocated the villagers so that they did not suffer badly on account of this damage. I know the problem of Brahmaputra. Hon. Prime Minister has taken several steps but the problem is so enormous. Brahmaputra is a very, very big river which is spread over thousands of miles. It is a big problem to be solved. I only appeal to the Government to provide more funds and ensure that the people who are residing on both sides of the river are protected by constructing the retaining walls so that villages are not damaged. I am really grateful to you for permitting me to speak. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Anthiyur P. Selvarasu. Hon. Member to speak in Tamil.

SHRI ANTHIYUR P. SELVARASU (Tamil Nadu): *"Hon. Deputy Chairman Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to speak on this year's Budget. The charges put forward by opposition parties, including DMK, against this Government are that you give incentives and benefits only to the private sector. If you pay attention to Public Sector Units, the profits earned by them will be utilised for the welfare of people.

Sir, Mumbai is considered as the Manchester of India. Similarly, Coimbatore is considered as the Manchester of South India. Coimbatore is an industrial city in Tamil Nadu. Now, more than 480 cotton mills have been closed. National Textile Corporation Mill also has been closed. As a result, lakhs of workers have become unemployed. They are skilled in various professions related to textile mills, but now they are seeking alternate employment. The situation in Coimbatore is tragic. When the reality is miserable, this Budget has spoken about giving incentives to new learners in skill development. It is not praiseworthy. Instead, the Government should consider giving employment to already skilled people.

Sir, I would like to mention some facts about the leather industry. It is a very important sector. People belonging to the Arunthathiyar community in Tamil Nadu were involved in tanning and leather processing. They belong to the Scheduled Caste community. Now they could not continue their profession due to the high rate of GST imposed on leather goods. The leather industry is regressing now. Students from this section should be given training at Central Leather Research Institute (CLRI) and employment opportunities have to be created for them. It would benefit the leather processing industry.

Sir, in the western districts of Tamil Nadu, there are many industries that engage in the manufacture of electric motors. They have been in this profession for a considerable time. But now these industries are on the verge of closure due to the high rate of GST imposed on them.There are many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the districts of Coimbatore, Erode, Tiruppur, Karur and Namakkal. They are severely affected due to the high rate of GST imposed on them. Many MSMEs are on the verge of closure. Government should pay attention to their plight and should make efforts to solve their crisis. People of these districts are involved in various professions such as working in knitting industries, hosiery units, garment industries, manufacturing of electric motors, poultry, eggs, livestock and animal husbandry, dairy farming, textile industries specialised in production of bedsheets and pillow covers, manufacturing spare parts for vehicles, the auto-body

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

building of lorries, and so on.They are very industrious employees and labourers. However, due to the high imposition of GST, many industries are closed. Lakhs of people are unemployed. There are thousands of diligent labourers living in the cities of Sangagiri, Tiruchengode and Namakkal. They should be given some financial assistance to continue their profession. Students belonging to SC/ST communities should be given scholarships on time. Many of the students are denied their scholarships. Steps should be taken for the proper disposal of scholarships.

I do not know what kind of plans the Government has formulated for people belonging to cottage industries. People engaged in cottage industries contribute significantly to the economy of the country. They have to be given GST exemptions. The Union Government's institutions such as Khadi and Village Industries Commission (KVIC) should assist them in marketing their products.The Government should encourage self-employment. They contribute significantly to the employment of this country. Youths who desire to be self-employed should be given loans at concessional rates of interest.

Sir, Erode City is popularly known as Turmeric City. It also excels in textile production. Its neighbouring town is Kangeyam. Both these cities are densely populated with diligent labourers employed in the profession of textile industry and also in the cultivation of turmeric crops. People from many states of India visit Erode for textile trade and turmeric trade. Having a railway overbridge in the Erode-Kangeyam rail route is a longstanding demand of the people of these cities. A petition is given to the concerned minister in this regard. Sir, I request the Government through you that it may be considered. A railway overbridge may please be built as expeditiously as possible.

Sir, I would like to mention a private college in Erode, Chikkaiah Naicker College. Its management could not run the college. The Government of Tamil Nadu had acquired that college. But there are certain practical difficulties in acquisition. A No Objection Certificate (NOC) has to be issued by the Union Government for acquiring this college. Accordingly, a petition has been given to the hon. Governor of Tamil Nadu. Now, the file is under consideration with the hon. President of India. Sir, I request the Government, through you, that the file may be signed as early as possible and NOC has to be given to the Government of Tamil Nadu to acquire the college so that students would benefit on time.

Sir, finally I would like to conclude by reiterating that this Government does not pay attention to Public Sector Units such as NLC and BSNL. Public Sector Units have to be protected. The Government has to pay attention to BSNL. Many employees are retiring voluntarily. Their problems have to be looked into and BSNL may be saved.

With these words, I conclude my speech. Thank you."

**प्रो. मनोज कुमार झा** (बिहार) **:** उपसभापति महोदय,

*"सुनेगा कौन मेरी चाक-दामनी का अफसाना,*
*यहाँ सब अपने अपने पैरहन की बात करते हैं।"*

माननीय उपसभापति महोदय... ...(**व्यवधान**)... मैंने इधर का इशारा किया। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति**: प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

**प्रो. मनोज कुमार झा**: माननीय उपसभापति महोदय, मैं बजट आने से पूर्व प्री-बजट कंसल्टेशन पर 30 सेकंड बोलूँगा। माननीय उपसभापति महोदय, प्री-बजट कंसल्टेशन होता है। मैंने उद्योगपतियों के साथ मीटिंग देखी, कॉरपोरेट हाउसेज़ के साथ मीटिंग देखी और मैं आज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों से प्री-बजट कंसल्टेशन में सीवर में उतर कर मरने वालों के प्रतिनिधिमंडल से बात नहीं होती। ठेला मजदूरों से बात नहीं होती। बेरोजगार युवकों से बात नहीं होती। छोटे-मझोले किसानों से बात नहीं होती और अब तो ट्रेड यूनियन से भी बात होने की रवायत बंद हो गई है। हाल के दिनों में, मैं राहुल रामगुंडम जी की जॉर्ज साहब पर एक किताब पढ़ रहा था। उसमें पता चला कि आज जिन चीज़ों के लिए लोग सदन में नाराज़ हो जाते हैं, जॉर्ज साहब उन चीज़ों के बगैर सदन में अपनी बात ही नहीं रखते थे, चाहे वह बिज़नेस हाउसेज़ का नाम लेना हो या इंडस्ट्रीयल पॉलिसी की बात हो। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि यह मैडम का सातवाँ बजट है। उनको बहुत बधाइयाँ मिलीं। सर, सात साल पुराना तो नहीं हूँ, छठी बार... मैं माननीया वित्त मंत्री जी के समक्ष आर्टिकल 39, क्लॉज़ सी और मैं चाहता हूँ कि इसे सब लोग पढ़ें कि हमारा बजट हमारे प्रिएम्बल में है - डिग्निटी, जस्टिस, इक्वेलिटी। हमारा बजट इसे कितना रिफलेक्ट करता है? आर्टिकल 39 (सी), जो concentration of wealth की बात करता है कि राज्य की कोशिश होनी चाहिए कि इस रूप में इनकम इनइक्वेलिटी न बढ़े। मैं नहीं बताना चाहता कि 90 प्रतिशत संसाधन किसके कब्जे में हैं। माननीय उपसभाति महोदय, आय की इतनी असमानता - परेशानी इस बात से होती है। यह मत समझिएगा कि मैं धन संचय का विरोधी हूँ या अमीरी का विरोधी हूँ, लेकिन अश्लील अमीरी और जिसका भौंडा प्रदर्शन हमने हाल के दिनों में देखा है, दिक्कत उससे है, इसलिए आय की असमानता पर बात होनी चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, मेरे साथी हमारी पार्टी से बोल चुके हैं। मैं मनरेगा पर एक-दो बात कहना चाहता हूँ। अपनी स्थापना से लेकर आज तक पहली बार मनरेगा पर उस रूप में जिक्र नहीं हुआ, जैसा होता रहा है। 86,000 करोड़ दिए गए। ...(**व्यवधान**)... सर, अभी मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। 86,000 करोड़, जो कि इंटरिम बजट के बराबर हैं। आपका actual expenditure 1,05,000 करोड़ था। 20,000 का गैप है और यह मैं इसके आधार पर कह रहा हूँ। मैं आंकड़े गढ़ नहीं रहा हूँ। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इससे क्या होगा - मजदूरी के भुगतान में देरी होगी, suppression of demand होगा और quality assets का निर्माण नहीं होगा।

माननीय उपसभापति महोदय, भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल विकास की योजनाओं में 50 लाख से ज्यादा स्कीम वर्कर्स हैं, जिनमें 90 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं। पांच वर्षों में उनके मानदेय में बढ़ोतरी की कोई कोशिश नहीं हुई है। महोदय, कोरोना का पूरा भार - किसकी लाश है, कौन बीमार है - इन्होंने उठाया है, चाहे वे आशा, ममता, आंगनवाड़ी, रसोईया आदि हों। कृषि पर अभी एक बड़ी आबादी निर्भर है। खेतिहर मजदूर, छोटे-मझोले किसानों की दिक्कतें अलग हैं। कृषि के आउटपुट का आंकड़ा भी सवालों के घेरे में है, लेकिन सवाल लेंगे नहीं। Legal guarantee to MSP. What stops you? प्लीज़, मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों पर खुलकर बात हो। सर, 2024 के मेनडेट की एक खास बात है और यह मैं पहले कह चुका हूं कि दोनों पक्षों के लिए एक संदेश है। हमारे लिए संदेश है, what we have done is not enough और उनके लिए संदेश है कि एक्नॉलेज करो कि दिक्कत कहां है। सर, इस बजट में एक्नॉलेजमेंट है। मैं इंकार नहीं करता हूं कि एक्नॉलेजमेंट है। प्राथमिकताओं की बात होती है। कहा गया कि सिर्फ चार जातियां हैं - गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता। सर, यह sociological anthropological instrument का बेजा इस्तेमाल है। सर, इस देश में जाति हकीकत है। मैं सौ दफा बोल चुका हूं और मैं कह रहा हूं कि जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे, आपका टारगेट स्पेसिफिक नहीं होगा, आपका बजट मीनिंगलैस होगा और आपकी नीतियां लोगों तक नहीं पहुंचेंगी। सर पर हाथ रखने से, आंख पर हाथ रख लेने से हकीकत नहीं बदलती है। I must tell you that you cannot kill the idea which has arrived. Caste census is that idea.

सर, बेरोजगारी को लेकर तकरीबन 27-28 करोड़ का बैकलॉग है। बेरोजगारी की कहानी अदभुत है। एक बड़ी आबादी disguised unemployment में है और कुछ under-employment में है। **...(समय की घंटी)...** सर, मैं बस एक-डेढ़ मिनट और लूंगा। कुछ उस सीमा को पार कर चुके हैं। आप इस बजट में 80 लाख की बात करते हैं। आपको प्रति वर्ष 5-6 करोड़ रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करनी होगी। तभी जाकर यह जो democratic dividend है, जो आप लोग कहते हैं, उसको आप एड्रैस कर पाएंगे। एमएसएमई सैक्टर, खासकर इसमें जो माइक्रो और स्मॉल है, आपने उसकी रीढ़ तोड़ दी है - चाहे डिमॉनिटाइजेशन हो, जीएसटी हो - रीढ़ तोड़ने के बाद सर्जरी चाहिए, बैन्डेड नहीं लगाना पड़ता है, आप बैंडेड लगा रहे हैं। Apprenticeship, internship के विषय में मैं एक ही बात कहूंगा, सर, बस मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा हूं। आप 5 हज़ार रुपया दे रहे हैं। एक तो कहते हैं, will nudge the corporate houses. मैंने nudge का हिन्दी अनुवाद देखा। वह कोहनी से धक्का मारना होता है। अब आप कॉर्पोरेट हाउस को कोहनी से धक्का मारकर कह रहे हो कि रख लो। सर, मैं बस एक मिनट और लूंगा। 5 हज़ार को 30 दिन से डिवाइड करिए, तो 166.66 रुपये आता है - यह तो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है। **...(समय की घंटी)...**

सर, आखिर में जय हिंद बोलने से पहले, बिहार को लेकर बड़ी बात हुई। सर, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। 2015 का प्रधान मंत्री जी का आरा वीर कुंवर सिंह की धरती का भाषण सुनिए, फिर टॉर्च या लालटेन लेकर स्किल यूनिवर्सिटी ढूंढ़िए, केंद्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर में ढूंढ़िए। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं - *"हमने लाखों के बोल सहे सितमगर तेरे लिए"*, तो मैं सितमगर से आग्रह करूंगा कि इन मुद्दों के मद्देनजर बजट को रीलुक दीजिए, बजट को आम आदमी का बजट बनाइए। जय हिंद सर! बहुत-बहुत शुक्रिया।

**श्री उपसभापति**: थैंक यू, मनोज कुमार झा जी। माननीय डा. दिनेश शर्मा जी।

**डा. दिनेश शर्मा** (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद, उपसभापति महोदय। काफी विद्वतजनों का उद्बोधन सुनने का सौभाग्य मिला है। मैं वाणिज्य का प्रोफेसर हूं और इतिहास मैंने बचपन में पढ़ा था। इतिहास में प्रसंग आता है कि महाभारत का युद्ध छिड़ा है और पांडव के योद्धाओं को लगता है कि ये कौरव के सारे योद्धा कहां चले गए।

2.00 P.M.

तो उनको कोई सूचना देता है कि वे पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए चक्रव्यूह बनाने गए हैं। आज के वातावरण में मैं किसी की तुलना कौरव और पांडव से नहीं करता हूँ, लेकिन इस संसद भवन में आज कांग्रेस विहीन, आम आदमी पार्टी विहीन, समाजवादी पार्टी विहीन और मुझे लगता है कि डीएमके विहीन भी, मैं यह परिदृश्य राज्य सभा में देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ गए होंगे, मैं तुलना भी नहीं कर रहा हूँ और न मैं यह कह रहा हूँ कि ये * बनाने गए होंगे, लेकिन निश्चित रूप में ये जहाँ भी होंगे, ये अपनी पार्टी के लिए कुछ न कुछ सोच रहे होंगे या देश में जो घटनाएँ हैं, उनके लिए कुछ न कुछ सोच रहे होंगे। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... No cross-talking, please. ...*(Interruptions)*...

**डा. दिनेश शर्मा**: यह एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा है और महत्वपूर्ण चर्चा के विषय में विपक्ष का निराशावादी दृष्टिकोण कि एक भी व्यक्ति उपस्थित न रहे, मैं समझता हूँ कि यह भी सदन के लिए चिंता का विषय जरूर होगा। तमाम बातें कही गईं। आज मैं आदरणीय काका श्री खरगे साहब का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने जिस भावपूर्ण शब्दों में आदरणीया वित्त मंत्री महोदया को माता जी कह कर संबोधित किया, तो पीठ ने टिप्पणी की कि वे आपकी बेटी के समान हैं, माता कैसे हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने सही कहा है। माता का जो दायित्व है, वह यह है कि वह घर में सबकी चिंता करती है। वह अपने लिए चिंता नहीं करती है, हर बच्चे की यथास्थान उसकी उपयोगिता की चिंता हो सके, घर के साधन-संसाधन को जुटाया जा सके, यह माँ का कर्तव्य होता है और वित्त मंत्री जी ने पूरे बजट में इन सारी चीजों का समाहन किया है।

जहाँ तक मैं देखता हूँ कि जैसे-जैसे बजट आते जा रहे हैं, उनमें जो आर्थिक संतुलन है, वह अपने आप में बढ़ता जा रहा है। बजट में अगर देखा जाए, तो कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपए का है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। सकल प्राप्तियाँ 25.83 लाख करोड़ है, जबकि वित्तीय घाटा 4.9 परसेंट पर आ गया है। यह पहले काफी ज्यादा था। इस बजट के साथ-साथ वित्त मंत्री ने संकल्पना की है कि जो अगला बजट आएगा, उसमें जो वित्तीय घाटा होगा, वह जीडीपी का 4.5 परसेंट होगा। यानी अभी से हमने अगले बजट में जो आय-व्यय का संतुलन है, उसको

* Expunged as ordered by the Chair.

स्थापित करने की सोच रखी है। यह एक visionary Budget है और visionary Budget इसलिए है, क्योंकि सरकार का घाटे का जो लक्ष्य था, वह लक्ष्य 4.5 परसेंट से नीचे लाने का था और उसकी तरफ हम तेजी से बढ़े हैं। हमारा लक्ष्य है कि मुद्रास्फीति कम हो, मुद्रास्फीति स्थाई हो और 4 प्रतिशत के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। मैं समझता हूँ कि इस संरचना में एक दूरगामी सोच का लक्षण दिखाई पड़ता है। इसमें हम देखें, तो हमने चहुँमुखी विकास की तरफ देखा है। यह जो कोर मुद्रा स्फीति है, यह 3.1 प्रतिशत पर आई है। यानी हमारी जो संभावनाएँ हैं, हम केवल भाषण नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज को एक तरीके से आय और व्यय का संतुलन, जिसको हम कहते हैं कि trade balance को favour में करने की हमने जो कार्ययोजना तैयार की थी कि हमारा निर्यात बढ़े, हमारा आयात कम हो, हमारा उत्पादन बढ़े, हमारे उपभोक्ता की माँग का सृजन हो और उपभोक्ता की माँग के सृजन के अनुसार हमारी पूर्ति को हम अपने आप से प्राप्त करते रहें। इन सारी चीजों में जहाँ हमने 4.1 करोड़ युवाओं के लिए 5 साल तक रोजगार कौशल को बढ़ाने की बात की है, वहीं अगर हम देखें, तो हमने राजकोषीय घाटे को जैसा मैंने पहले कहा कि हम 4.9 प्रतिशत पर लाए हैं। हमारा GDP दसवीं अर्थव्यवस्था से आज पाँचवी अर्थव्यवस्था पर आया है। आप सब बार-बार बेरोजगारी की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन कम हो रही है। अगर हम पिछले से पिछले वर्ष की तुलना करें, तो 2021-22 में यह 4.1 परसेंट थी, तो आज यह 3.2 परसेंट है। भारत अमेरिका को पछाड़ रहा है, ब्रिटेन को पछाड़ रहा है। आज डिजिटल लेन-देन 12 हजार करोड़ से ऊपर पहुँच चुका है। यह भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक सिग्नल है। शायद उसकी गूँज किसी को कम सुनाई पड़ती होगी, लेकिन यहाँ की जनता को पूरी तरह सुनाई पड़ रही है।

सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभूतपूर्व काम हुए हैं। पहले 8,29,409 किलोमीटर की मंजूरी दी गई थी और यह पहली सरकार है, जिसने उसमें से 7,63,308 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा कर लिया है। यानी सड़क निर्माण के मामले में आज अगर देखा जाए, तो जो पिछली सरकार थी, पिछली से पिछली सरकार थी, उसके समय में, 2013-14 में केवल 25,859 करोड़ का काम हुआ था। वहीं हमारी सरकार में अगर 2024-25 में देखें, तो 78 हजार करोड़ के आसपास का सड़क निर्माण का काम हुआ है।

कांग्रेस के हमारे एक विद्वान वक्ता रेलवे के बारे में कह रहे थे कि उसमें कोई काम ही नहीं हुआ है। अगर कोई काम नहीं हुआ, तो 2,55,393 करोड़ का बजट कहाँ से आया? आप कहते हैं कि रेलवे में काम नहीं हुआ, तो अगर आप देखें तो 2013-14 में कांग्रेस सरकार के समय रेलवे में केवल 28,174 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। आज हम इसमें कई गुणा ज्यादा काम कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए, तो हर क्षेत्र में काम हुआ है। रोजगार सृजन का एक अमृत बाण अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। वह क्या है - हमने एंजल टैक्स को हटाया है। हम स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहन देने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने 100 शहरों में निवेश के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास करने की संकल्पना रखी है। आज अगर देखें, तो पूरे के पूरे भारतवर्ष में रेल जो एक जीवनरेखा थी, उसके रूप में वह सामने आई है। आज रेलवे के सामान वाली 40,000 बोगियों को वंदे भारत ट्रेन के अनुरूप बनाया जा रहा है। यह सबसे बड़ी बात है।

मान्यवर, वे पूछते हैं कि क्या हो रहा है - यह हो रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं। जिस देश का, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहाँ साढ़े 3 प्रतिशत की ग्रोथ अपने

आप में बढ़ जाती है। यह बड़ी बात है। यह सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रही है। आप देखें तो अब हमारे 157 हवाई अड्डे हो गए हैं, हमने बंदरगाहों का पूरी तरह से जीर्णोद्धार किया है, उनको नया बनाया है, हमने रेल मार्गों को दुरुस्त किया है, हमने सड़क मार्गों को दुरुस्त किया है। इस प्रकार हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का काम किया है। हम यह कह सकते हैं कि हमारे जो मध्यमवर्ग के भारतीय हैं, उनकी रेल यात्रा सुगम हो, उनमें सुरक्षा हो, उनमें सुविधाएँ बढ़ाई जाए, हमने इसकी चिन्ता की है।

मान्यवर, कभी-कभी इस बात की चिन्ता होती है कि अचानक चुनावों में अफवाहें उड़ीं। अफवाहों में - आरक्षण के विषय में अफवाहें उड़ीं, चुनावों में संविधान परिवर्तन की अफवाहें उड़ीं, उसके बाद विभिन्न प्रकार के बजट की चर्चाओं की अफवाहें उड़ीं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि माननीय रेल मंत्री जी इस बात की जाँच जरूर करायेंगे कि अचानक - अगर आप इस एक हफ्ते को देखें, तो रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने का क्रम कैसे शुरू हुआ? कहीं यह किसी साजिश का अंग तो नहीं है? आज सरकार को किस प्रकार से कमजोर किया जाए - आरोपों के आधार पर, * के आधार पर, मिथ्या वर्णन के आधार पर? येन, केन, प्रकारेण, किस प्रकार से सरकार कमजोर हो, इसका यह जो एक क्रम चला है, मैं समझता हूँ कि भारत के लोकतंत्र के लिए यह दुखदायी है। आज हम कह सकते हैं कि विभिन्न रूपों में हमारी सरकार ने जहाँ किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम किया है, वहीं वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी तमाम प्रकार की योजनाएँ लायी है। ...(**समय की घंटी**)... मान्यवर, सभी को 5-10 मिनट का समय मिला है।

**श्री उपसभापति**: 10 मिनट नहीं, 2-3 मिनट।

**डा. दिनेश शर्मा**: अभी आप पाँच वक्ताओं का देख लीजिए। सभी को 5 मिनट से ऊपर का समय मिला है।

**श्री उपसभापति**: आप 2-3 मिनट और बोल लें।

**डा. दिनेश शर्मा**: मान्यवर, मैं यह कह सकता हूँ कि हमने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी जो मानक कटौती थी, उसे 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये की है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के जो अन्य प्रयोजन थे, उन पर भी हम आगे आए हैं। हमने 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' के लिए 14,600 करोड़ रुपए आवंटित किया है। किसानों की आमदनी बढ़ सके, उसके लिए हमने उपाय किए हैं।

ये बार-बार कहते हैं कि आपने एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं की। अगर आप तुलना देखें, तो जहाँ 2013-14 में काँग्रेस की सरकार में धान का एमएसपी 1,310 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं आज भाजपा सरकार या एनडीए सरकार के समय धान का एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल है। गेहूँ का एमएसपी 2013-14 में जो 1350 रुपए प्रति क्विंटल था, वह आज 2,275 रुपए प्रति क्विंटल है।

* Expunged as ordered by the Chair.

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुए हैं और पठन-पाठन की प्रक्रिया में तेजी से सुधार हुआ है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। अगर आप देखें, तो कोरोना के समय भी हमारी सरकार ने डिजिटल एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया, 'ज्ञान गंगा' को दूरदराज गाँवों तक पहुँचाने में ऐतिहासिक सफलता पाई।

[**उपसभाध्यक्ष** (**श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला**) *पीठासीन हुए।*]

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश का एक उद्धरण देना चाहता हूँ। एक तरफ कोरोना की मार थी, तो दूसरी तरफ हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों ने एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन किया और परिवर्तन के साथ डिजिटल रूप में पठन-पाठन की प्रक्रिया को शुरू किया। इसके साथ ही टीचर्स के लेक्चर्स को डिजिटली अपलोड कराया गया। 78 हजार टीचर्स के लेक्चर्स अपलोड हुए और ये 78 हजार लेक्चर्स पूरे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पठन-पाठन के लिए उपलब्ध हुए। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने आकर उस डिजिटल लाइब्रेरी की तारीफ की, जिसको कोरोना काल में भाजपा सरकार के द्वारा बनाया गया था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार की प्राथमिकता यह रही कि गुणवत्तापरक शिक्षा हो, सुखी मन शिक्षक हो, नकल विहीन परीक्षा हो और तनाव मुक्त विद्यार्थी हो। आप देख रहे हैं कि शिक्षा का बजट बढ़ा है। जहाँ 2013-14 में 65,867 करोड़ रुपए का बजट था, वहीं आज 2024-25 में 1,20,627 करोड़ रुपए का बजट है, यानी निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। आज 319 नए मेडिकल कॉलेज और 15 एम्स हैं। **...(समय की घंटी)...** जो 2015 में केवल 11 थे, आज वे 46 हो गए हैं। इनमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज शैक्षिक सुधारों का युग है, आर्थिक सुधारों का युग है। यह युवाओं के रोजगार सृजन का युग है। आज के समय हम एक उस पीढ़ी को देख रहे हैं, जो 2047 में एक विकसित भारत की जो एक संकल्पना है, उसको हकीकत में बदल सके। यह बजट युवाओं के सपनों को पंख लगाने वाला बजट है। यह बजट 2047 में विकसित भारत का जो विज़न है, उसको हकीकत में बदलने वाला बजट है। यह एक संतुलित बजट है। यह हमारी deficit financing, जो हमारी घाटे की वित्त योजना है, उसको कम करने वाला, एक पूँजीगत व्ययों को नियंत्रित करने वाला बजट है। इस बजट का यह प्रभाव होगा कि आने वाले समय में हमारी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, रोजगारों में वृद्धि होगा और हमारा उत्पादन बढ़ेगा। मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि भारत में जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए इस देश में उपभोक्ता ज्यादा हैं। अगर हम उत्पादन ज्यादा करते हैं, तो उसका उपभोग करने वाले लोग हैं, यानी उसकी माँग की पूर्ति करने के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध हैं। इसलिए इस बदली हुई सरकार में मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा। मैं फिर से कहूँगा कि मैंने आदरणीय खरगे जी को काकाश्री कहा है। यह असंसदीय शब्द नहीं है। उन्होंने माता स्वरूप में देखा था, लेकिन एक दिन खरगे जी ने कहा था कि मैं जो कुछ हूँ वह आदरणीय सोनिया दादी माँ के कारण हूँ, आदरणीय राहुल चाचा जी के कारण हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो सानिध्य की प्राप्ति है, वह मैं यहाँ पर देख नहीं पाया, लेकिन उन्होंने बजट की प्रशंसा की, इसलिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Is it allowed to take the name of a Member who is in the other House? *...(Interruptions)...*

**डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र)** : #"उपसभाध्यक्ष जी, अमृत से भी मीठी मराठी भाषा में आज मैं बोलने वाला हूं । प्रभु चक्रधर स्वामी ने इस मराठी भाषा की नींव डाली । संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत बहिणाबाई जैसे संतों ने इस भाषा को समृद्ध किया, तथा अनेक साहित्यकारों ने इसकी सुदंरता में योगदान दिया। ऐसी मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, ऐसी भावना से भी मैं बात कर रहा हूं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे अच्छी मराठी बोलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, जो हमारे सांसद भी थे, वे भी अच्छी मराठी बोलते थे और भारत को विकसित भारत बनाने के बारे में बार बार अपनी बात कहनेवाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी कई बार मराठी में बात करने का आंनद लेते हैं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र सदन में एक कार्यक्रम के दौरान अपना भाषण खत्म होने के बाद प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने मराठी में कहा, चलो अब भूख लगी है, खाना खा लेते हैं और उनके इस मराठी संवाद से हम सांसद भोजन से पहले ही तृप्त हो गये ।

उपसभाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2024-25 के लिए जो बजट पेश किया है वह किसान, युवा, वीर जवान, महिला, मध्यम वर्ग और गरीबों का बजट है, इसलिए मैं इसका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला और वित्त मंत्री जी का सातवां बजट पेश किया गया है, जिसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद बोल सकते हैं, लेकिन * नेरेटिव फैलाने वाले वे लोग होते हैं, जो हमारे गांवों मे जैसे कौए शोर करके पूरे गांव को संभ्रम में डाल देते हैं, वैसे बोलना शुरू कर देते हैं। महाराष्ट्र मे तो ऐसा संभ्रम फैलाने वाले अनेक लोग हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्य मंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने बहुत जल्दी ऐसे ** नैरेटिव का पर्दाफाश करने का प्रयास किया। हमारी बहन डॉ. मेधा कुलकर्णी ने इस बजट में महाराष्ट्र को क्या दिया गया है, इसका विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन दो बातें मैं कहने वाला हूं जो महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार के द्वार खोलनेवाली हैं। महोदय, गढ़चिरोली एक ऐसा जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय और भारत की प्रति व्यक्ति आय से भी कम है। यह एक आकांक्षी जिला है। यह आदिवासी जिला भी है। 1984 में माओवादियों ने यहां अपने अधिवेशन में कहा था कि भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र हमें मंजूर नहीं, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार हमें मंजूर नहीं, हम सरकार स्थापित करेंगे। और तबसे यहां नक्सलवाद और माओवाद बढ़ता गया। इस नक्सलवादी हिंसा में कई युवा, ग्रामीण लोग अपनी जान गंवा बैठे, और कई पुलिसकर्मी शहीद हुए। उसी गढ़चिरोली के सुरजागढ़ में जिस स्टील उद्योग का शिलान्यास उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस और उप मुख्य मंत्री अजीत पवार ने हाल ही में किया, उस स्टील उद्योग से इस जिले के आदिवासी युवाओं को रोजगार के नए

---

# Hindi translation of the original speech delivered in Marathi.

* Expunged as ordered by the chair.

अवसर मिलेंगे। इसमें 7 हजार आदिवासी युवकों को नौकरियां मिलेंगी और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी सोचते हैं तो सिर्फ विकसित भारत के लिए।

महोदय, केन्द्रीय मंत्री परिषद ने महाराष्ट्र के लिए 72 हजार 220 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले वाढ़वण बंदरगाह को मंजूरी प्रदान की। डहानू के नजदीक यह बंदरगाह बनने वाला है। इसके विकास के लिए मंत्री परिषद ने हरी झंडी दिखाई है। जे.एन.पी.टी. और महाराष्ट्र मैरी टाईम बोर्ड दोनों मिलकर इस वाढ़वण बंदरगाह का निर्माण करेंगे। 2029 तक इसका पहला हिस्सा पूरा होगा। 2037 तक दूसरा हिस्सा तैयार होगा। सिंगापुर और कोलंबो के बाद यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह बनेगा। आज दुनिया में बड़े कन्टेनर समुद्री व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज भारत में ऐसे कन्टेनरों को समुद्र में खड़ा करने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। 2001 में कामराज बंदरगाह तैयार हुआ था, उसके बाद दो दशकों में यह पहली सरकारी परियोजना है, जिसके अंतर्गत इस बंदरगाह का निर्माण होना वाला है । मैं यह बताना चाहूंगा कि इस वाढवण बंदरगाह से 12 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी और उनमें से 90 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।

लेकिन दुर्भाग्य यह है कि महाराष्ट्र में उबाठा एक ऐसा नाम है जो विकास की परियोजनाओं का हमेशा विरोध करता है। चाहे वह मैट्रो फेज़ 3 हो, चाहे कोस्टल रोड हो, चाहे जैतापुर की अणुऊर्जा परियोजना हो, चाहे खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाने की बात हो और चाहे इस वाढ़वण बंदरगाह की बात हो, इन सब के लिए उबाठा का विरोध है। वहां स्थानीय लोगों को भड़काया जा रहा है। और कुछ मानवाधिकार संगठन, जिन्होंने इससे पहले नर्मदासागर परियोजना का विरोध किया था, वही अब इस बंदरगाह के विरोध में खड़ी हुई हैं। और इसलिए उबाठा हो या अन्य कोई, मेरा उनसे कहना है कि यह मोदी जी की विकसित भारत की पहल है जिसमें 12 लाख युवाओं को नौकरियां मिलनी वाली हैं। ...(व्यवधान)... और मेरी विनती है कि कुछ माननीय सदस्यों को उबाठा नाम से भले ही आपत्ति हो, लेकिन यह उबाठा ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरा महाराष्ट्र बर्बाद करने की ठान ली है। पेयजल की कोई योजना हो चाहे कोई सिंचाई परियोजना हो, इन सबका विरोध करने वाला यह उबाठा है और इसलिए लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वाढ़वण बंदरगाह से 12 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। पालघर जैसे आकांक्षी जिले में ये नौकरियां मिलेंगी। महोदय, उबाठा शब्द रिकार्ड से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह असंसदीय नहीं है।"...(व्यवधान)...

और इसलिए सभापति जी एक और महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि अग्निवीर के बारे में मै बात करने वाला हूं क्योंकि सर, अग्निवीर ऐसा है, जो पूरे भारत का संरक्षण का नक्शा बदलने वाला है। महोदय, आपको पता है कि संरक्षण की क्षमता बढ़ाना ज़रूरी है। ...(व्यवधान)... संरक्षण की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने हर बजट में ज्यादा allocation रखा है। ...(व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला):** प्लीज़, आप बजट पर बोलिए। Please do not criticize. ...*(Interruptions)*... Please speak on Budget ...*(Interruptions)*...

**डा. अनिल सुखदेव राव बोंडे:** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA): Do not deviate. Please do not deviate. ...*(Interruptions)*...

**डा. अनिल सुखदेव राव बोंडेः** क्योंकि अग्निवीर के बारे में पूर्व वित्त मंत्री, जिन्होंने बोला था कि हमारी सत्ता आएगी तो हम अग्निवीर योजना को निकाल देंगे। ...(**व्यवधान**)... लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि यही वे वित्त मंत्री थे, जिन्होंने digital transaction के लिए नेगेटिव बोला था। यही वे वित्त मंत्री थे, जिन्होंने बोला था कि भारत में digital transaction नहीं हो पाएगा। कल आरबीआई की रिपोर्ट आई कि भारत digital transaction में सबसे बड़ा देश, एक नम्बर का देश हो रहा है।

इनकी ऐसी नेगेटिव मानसिकता है और अग्निवीर के बारे में सोच ऐसी है कि पूरी forces की उम्र - आज हमारी forces की average age 37 years है। महोदय, फोर्स चुस्त होनी चाहिए, यंग फोर्स होनी चाहिए। यू.एस. की average age 23 years है, पाकिस्तान की average age 22 years है, चाइना की average age 22 to 23 years है और हमारी average age 37 years है। कांग्रेस के समय में, यूपीए के काल में हर बार जब force में भर्ती होती थी, तब 10,000 से ज्यादा recruitment कभी नहीं होता था। और जब 10 हजार से कम recruitment होती हैं, तो 37 से एवरेज ऐज कभी कम नहीं हो सकती। Central Defence Force, इन्होंने जो सुझाव दिया कि अग्निवीर के माध्यम से हम ज्यादा भर्ती कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को ले सकते हैं और ज्यादा लोगों को लेने के बाद में फोर्स की एवरेज ऐज कम हो सकती है। क्या यह नया है? 1947 से फौज में भर्ती होने वाले दो टाइप के लोग होते हैं -एक short service commission वाला और दूसरा permanent service commission वाला। Short service commission वाला पांच साल के लिए, दस साल के लिए रहता था। उसको भी ऑप्शन मिलता था कि वह परमानेंट सर्विस कमीशन में जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी short service commission वालों को पेंशन मिली है, क्या उन्हें कभी कैंटीन की सुविधा मिली है? उन्हें कभी नहीं मिली है। जैसे ऑफिसर्स के लिए था, वैसे ही कैडेट के लिए है। आज आपको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में armed forces में तीन बार 40,000 की recruitment हुई, 1,20,000 की recruitment हुई। 2026 तक 1,75,000 की recruitment हो जाएगी। एयर फोर्स में 4,950 की recruitment हुई, नेवी में 3,875 की recruitment हुई और यह अग्निवीर 17 से 21 के बीच में, दसवीं पास हुआ, जिसको 45 परसेंट मार्क्स मिले, तो वह अग्निवीर के लिए क्वालिफाई हो सकता है। आज नागपुर में इंटरव्यू शुरू है। नागपुर में साढ़े सात हजार सेंट्रल ज़ोन से अग्निवीर की भर्ती हो रही है। हमारे गांव का बच्चा, जो गरीब घर का बच्चा है। महाराष्ट्र की महारेजिमेंट थी, महाराष्ट्र की मराठा रेजिमेंट थी, महाराष्ट्र से कितने तोपी वीर निकलते हैं, यह अच्छा हेल्दी बच्चा, 17 साल का बच्चा जब जाता है, तो वह वहां पर चार साल ट्रेंनिग पाएगा, उसको 30 हजार रुपये महीना मिलेगा, 21वें साल में या तो 25 परसेंट बच्चे परमानेंट सर्विस में जाएंगे, जैसा short service commission में कहा गया है, वैसे परमानेंट सर्विस कमीशन में जाएंगे। 75 परसेंट बच्चे, जो trained होगें, जो disciplined होंगे, जो dedicated होंगे, वे सिविल सोसायटी में आएंगे। यह हमारे यहां ही नहीं है, बल्कि इजरायल में है, यूएस में है और ब्रिटेन में भी है। यह 75 परसेंट फोर्स भारत की reserved force रहेगी। आज

CAPF है, CRPF है, पुलिस की फोर्स है, बड़े-बड़े प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनकी भी कंपनीज़ हैं और वे चाहते हैं कि disciplined और dedicated लड़के मिलने चाहिए। और क्या असत्य बोलते हैं। असत्य बोलते हैं। वे असत्य बोलते हैं कि उसके शहीद होने के बाद में कुछ नहीं मिला है, लेकिन डिफेंस के प्रवक्ता ने बोला कि शहीद की फैमिली को एक करोड़ रुपये मिले हैं। आज तक 1,20,000 भर्ती हुई हैं। जो 18 लोग शहीद हुए, उनको भी मुआवजा मिला है और उनके ऊपर सभी को गर्व है, लेकिन fake narrative फैलाते हैं। मैं तो चक्रव्यूह, पद्मव्यूह बोलने वालों को बताना चाहता हूं कि कमल नाजुक दिखता है, लेकिन कमल की डंडी, कमल का दांडा मजबूत होता है। कमल के रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, वे फैलते हैं और बड़े ताकतवर होते हैं। कमल को मत छेड़ो। मैं संवैधानिक चेतावनी दे रहा हूं कि कमल को मत छेड़ो। जितना कमल को छेड़ोगे, उतना दलदल में फंसते जाओगे और दलदल में जितना उछल-कूद करोगे, पानी में कर सकते हैं, दलदल में नहीं कर सकते। दलदल में ज्यादा उछल-कूद की, तो और गर्त में जाओगे, पूरे डूब जाओगे, अंत पाओगे। ...(**समय की घंटी**)...

महोदय, सिर्फ किसानों के बारे में दो मिनट बोलना है।...(**व्यवधान**)... दलहन और तिलहन की आत्मनिर्भरता के लिए बजट में पहल की है। क्योंकि विकसित भारत के लिए यह मोदी जी की सोच है। 2018 से 2022 तक दलहन में बढ़ोतरी हुई है और 2027 तक हम ऑयल और खनिज में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, क्योंकि यह मोदी जी की सोच है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला)**: बोंडे जी, आपके बोलने का टाइम खत्म होता जा रहा है। आप कम्प्लीट करिए।

**डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे**: वेजिटेबल्स के लिए पहली बार प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत के लिए, यह मोदी जी की सोच है। मैं आखिर में, आपको बताना चाहता हूं कि जनता समझती है और जनता जानती है कि

*"मोदी को दूर करने की है आपकी आकांक्षा,*
*लेकिन अफसोस है कि जनता को है मोदी से विकसित भारत की आशा।'*
आप हो बिना भरोसे के... "

आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता,

*"आप हो बिना भरोसे के, इसलिए जनता कर रही है आपकी उपेक्षा।*
*कितना भी करो उछल-कूद, आपके नसीब में आएगी बार-बार निराशा"।*

इसलिए मैं देश को दिशा देने वाले विकसित भारत के अर्थ संकल्प का स्वागत करता हूं, अर्थ मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। नरेन्द्र मोदी जी लोगों की आशा हैं, क्योंकि वे विकसित भारत बना सकते हैं, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद। जय हिंद!

**उपसभाध्यक्ष (श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला)**: श्री अजीत कुमार भुयान। आपके पास बोलने के लिए 5 मिनट का समय है।

**श्री अजीत कुमार भुयान** (असम): थैंक यू वाइस चेयरमैन सर।

*"दिल धड़कता है नॉर्थ-ईस्ट के लिए।*
*पर दिल भड़कता है आंध्र और बिहार के लिए।*
*मैं तो खोजता रहा और तुम गुम होते रहे नॉर्थ-ईस्ट से।"*

Sir, I am from Assam and the lone voice of Opposition from the North-East in the Upper House. I will only speak about the North-East in the limited time allotted to me.

The Union Budget 2024-25 has given a stepmotherly treatment to the entire North-Eastern States. And, one can understand that Modi Government has punished Manipur, Nagaland, Meghalaya, and Mizoram for NDA-rout in the just concluded Lok Sabha polls. But, Assam, Tripura and Arunachal Pradesh have given fifteen Lok Sabha seats, out of eighteen, to the NDA. But, no major project or programme has been announced, except a half-hearted flood management mitigation scheme.

Sir, there has been consensual demand from all political parties of Assam that Assam flood devastation should be declared a national calamity. But, the Budget has given only a token treatment. I fail to understand why the Chief Minister of Assam and the Union Minister, Mr. Sonowal, had been completely ignoring the interests of the State just to keep their position in the Government intact. The Chief Minister of Assam terms the Budget as a game-changer for the State. But, the people of the State term the Chief Minister as '*Kumbhkarana*' for ignoring the legitimate and just concern of flood-affected people. The double-engine Government is there in all the North-East States. But, all the North-East States have been treated as Opposition-ruled States and all the Chief Ministers have lost their moral vibration to raise their respective financial difficulties as the said Budget has no capsule to address the financial disorder.

This Budget will further usher in anti-development mode in North-East, particularly in Assam, as the cycle of flood devastating in Assam has become a routine act of divine power year-after-year and the Government remains a mute spectator. In the current floods, more than 100 people have died. But there is nothing for Assam and the North-East. Since 2014, Modi*ji* and his Government have claimed that the Union Ministers visit North-Eastern States every third day and that the number of such visits may have crossed beyond count. However, do such visits have

a sustainable impact in terms of growth and development? Here, I want to know from the Government: When did oil royalty increase in the last 10 years of Modi*ji's* rule? The Assam silk is unique, but what has the Government of India done to promote Assam silk at the national level? The entire North-East Region has very high-level potential in the tourism sector but there is no intent to rejuvenate the tourism sector in the region. It has not been addressed to in the Budget. The Prime Minister always claims that the North East Region has been his priority but the people of the region have different notions because of the fact that there is nothing in this Budget for the North-East Region. Sir, I conclude by a couplet.

*"न कर तमाशा मेरी चुप्पी पर*
*जिस दिन हम टकरा जाएंगे*
*तुम्हारे तमाशे पर*
*पता नहीं कि तुम रहो कि मैं रहूं*
*पर एक बात है पक्की*
*कि कल तो मिट जाएंगे*
*यह बात है पक्की।"*

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA): Thank you, Ajit*ji*. Now, Dr. Bheem Singh; you have 10 minutes.

**डा. भीम सिंह** (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सभा यूनियन बजट 2024-25, जो 23 तारीख को माननीया वित्त मंत्री जी द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उस पर विचार-विमर्श कर रही है। अनेक माननीय सदस्यों ने इस पर अपने-अपने विचार रखे हैं और इन विचारों से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। यह जो बजट है, इस बजट को ऐसे समय पर प्रस्तुत किया गया है, जब पूरी दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ा हुआ है।

महोदय, एक समय यूपीए शासन का भी था, जब दुनिया बोलती थी और भारत सुनने के लिए मजबूर होता था, लेकिन आज 2014 के बाद स्थिति बदल गई है। आज जब भारत बोलता है, तो पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है। यह कैसे हुआ, यह करामात कैसे हुई और यह परिवर्तन कैसे हुआ? महोदय, यह परिवर्तन आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के मजबूत एवं कुशल नेतृत्व के कारण हुआ है। श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हिंदुस्तान की सामरिक शक्ति बढ़ी है, आर्थिक शक्ति बढ़ी है, इसलिए दुनिया आज हमारी बातों को सुनने के लिए मजबूर है और खुशी-खुशी सुनती भी है।

महोदय, दुनिया की डिप्लोमेसी में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। पहले सामरिक राजनय चलता था, डिफेंस डिप्लोमेसी, वॉर डिप्लोमेसी चलती थी, लेकिन आज धीरे-धीरे उसका स्थान आर्थिक राजनय ने ले लिया है, यानी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ने ले लिया है। महोदय,

हिंदुस्तान एनडीए के शासन में, आदरणीय प्रधान मंत्री जी के शासन में आर्थिक रूप से काफी मजबूत देश बनकर उभरा है।

महोदय, जब नरेन्द्र भाई मोदी शासन में आए, उस समय हिंदुस्तान दुनिया के आर्थिक जगत में 11 वीं पोजिशन पर था, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज दुनिया में पाँचवें स्थान पर पहुँच गया है और हम शीघ्र ही तीसरे स्थान पर जा रहे हैं। चूँकि हम एक सामरिक शक्ति के साथ-साथ, चाँद और मंगल पर जाने वाले के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गए हैं, चूँकि रुपया मजबूत हुआ है, इसलिए दुनिया हमारी बातों को ध्यान से सुन रही है। इसी कारण से, यह बजट 48,00,000 करोड़ रुपये का है। एक यूपीए के शासनकाल का समय था, जब बहुत मुश्किल से 12-13 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत होता था, लेकिन आज उससे चार गुना ज्यादा, 48,00,000 करोड़ रुपये का बजट हमारी सरकार लाई है। इसका श्रेय हमारे कुशल नेतृत्व को जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरी, यह आखिर कैसे हुआ, तो आप गौर करेंगे कि हमारी सरकार ने करप्शनलैस भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है। कर का आधार बढ़ाया है, टैक्स बेस बढ़ाया है। टैक्स कलेक्शन बढ़ाया है। लीकेज को समाप्त किया है, इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। टैक्सेशन पर भी हमारी सरकार काफी अच्छी नीति पर चल रही है।

महोदय, मैं बिहार से आता हूँ और इस बिहार को गौरव प्राप्त है, देश को चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे बेटे देने का गौरव प्राप्त है। चाणक्य, जो कौटिल्य ही हैं, चाणक्य और कौटिल्य एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा कि शासक को कर का संग्रह ऐसे करना चाहिए, जैसे मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं। इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि जिस तरह से मधुमक्खी फूलों को क्षति पहुंचाए बगैर टैक्स वसूलती है और फिर उसे मधु में परिवर्तित कर देती है, उसी तरह से शासक को चाहिए कि जनता से कर वसूले और उसको फिर उसी की सेवा में लगा दे। हमारी सरकार ने यही किया है। हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। सबका साथ, सबका विकास हमारी सरकार का नारा है। ...(**व्यवधान**)... महोदय, जो यह बजट है, इस बजट से कोई भी क्षेत्र, कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है। गाँव हो या शहर, किसान हो या मजदूर, छात्र हो या नौजवान, नागरिक हो या सैनिक, पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, कोई भी क्षेत्र, यहाँ तक कि अंतरिक्ष हो या समुद्र, सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार का हस्तक्षेप है और सभी के लिए कुछ-न-कुछ किया है। हमें खेद है कि इतने अच्छे बजट की, इतने महत्वाकांक्षी बजट की भी विपक्ष के द्वारा, खास तौर पर काँग्रेस पार्टी के द्वारा आलोचना की जा रही है। उस आलोचना में जो काँग्रेस के विरोध से जन्मी हुई पार्टियाँ हैं, जैसे 'तृणमूल काँग्रेस' 'काँग्रेस' के विरोध में जन्मी है। राष्ट्रीय जनता दल, जो गैर-काँग्रेसवाद के कारण ही पैदा हुई है, ऐसी पार्टियाँ भी काँग्रेस का साथ दे रही हैं। काँग्रेस की बात तो समझ में आती है कि उसके पेट में मरोड़ा क्यों हो रहा है। खिसियानी बिल्ली खम्भा नोंचे। उसे यह पच नहीं रहा है कि कोई गरीब घर का बेटा, कोई चाय बेचने वाले का बेटा, कोई पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ बेटा, नरेन्द्र मोदी तीसरी बार कैसे प्रधान मंत्री बन गया है। यह राष्ट्रीय जनता दल और इसकी सरीखी जो पार्टियाँ हैं, वे जब विरोध करती हैं, तो बड़ा दुख होता है। आलोचना का आधार क्या है? क्या कोई तर्क दे रहे हैं, क्या अपनी आलोचना का कोई औचित्य बता रहे हैं? कोई भी आधार नहीं है, लेकिन इनकी बातों से पता चलता है कि इन्हें दो शिकायतें हैं। एक शिकायत इनके वक्ताओं ने की कि यह घाटे का बजट है। मित्रो, घाटे का बजट! यह लाभ का बजट सरकार नहीं प्रस्तुत करती है। यह कोई वाणिज्यिक

कंपनी नहीं है, जो लाभ का बजट प्रस्तुत करेगी, यह जनकल्याण के लिए समर्पित सरकार का बजट है। अर्थशास्त्र में जो घाटे का बजट होता है, वह अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऋण लेकर भी हम जनता का विकास करते हैं। हमें नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने घाटे का बजट प्रस्तुत किया। दूसरा, इनकी आलोचना का आधार बना है, बार-बार उठा है और आज भी उठा है - बजट शब्द जितनी बार भाषण में आया, हमको लगता है कि उससे थोड़ा ही कम बिहार और आंध्र प्रदेश शब्द आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार से इतनी क्या शिकायत है, आंध्र से आपको क्या शिकायत है? अगर नरेन्द्र भाई मोदी जी ने इन पिछड़े हुए इलाकों की झोली में एक-एक मुट्ठी ज्यादा चावल डाल दिए, तो आपको क्या शिकायत है? यह कांग्रेस पार्टी हमेशा से बिहार की विरोधी रही है। मैंने इसी सदन में 22 तारीख को कहा था कि बिहार के प्रति जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अभी जो यह कांग्रेस पार्टी है, उसका कोई ध्यान नहीं रहा। पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। वह बनना चाहिए था, यह अच्छा है। पंजाब का काफी योगदान है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस भाखड़ा नांगल बांध की जो परियोजना थी, वह पहले बिहार में गई थी। नेपाल से जो बाढ़ का पानी आता है। वह बिहार को ध्वस्त कर देता है। ...(**समय की घंटी**)... उस पर डैम बनाने के लिए योजना थी, लेकिन वह नहीं बनाया गया और उसको वहां से हटा दिया गया। घंटी बज गई है, मेरे पास बहुत सी बातें थीं कि बिहार की कैसे उपेक्षा की जाती रही। कांग्रेस पार्टी ने बिहार की उपेक्षा की इसीलिए उसको आज विशेष सहायता की जरूरत पड़ी। मैंने डैम की बात भी की। महोदय, मैं दो-तीन मिनट का समय और चाहूंगा।

**उपसभाध्यक्ष** (**श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला**)**:** भीम सिंह जी, आपका टाइम खत्म होता जा रहा है।

**डा. भीम सिंह**: सर, बस दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

**उपसभाध्यक्ष** (**श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला**)**:** प्लीज़, अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए।

**डा. भीम सिंह**: आजादी के बाद केंद्र के द्वारा दो नीतियां बनाई गईं। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, माल भाड़ा समानीकरण की नीति - तब बिहार और झारखंड मिलकर एक बिहार राज्य था और इस माल भाड़ा समानीकरण की नीति के कारण बिहार को काफी घाटा हुआ। यह माल भाड़ा समानीकरण की नीति क्या थी - नीति यह थी कि जो बिहार में खनिज है, वहां जितने मूल्य में वह खनिज या वस्तु मिलेगी ...(**समय की घंटी**)... उतनी ही देश की किसी राज्य में भी जाकर, ढोकर मिलेगी। इसलिए वहां कल कारखाने कम लगे। दूसरी एक नीति बनी - रॉयल्टी की दर, वेट बेस्ड रॉयल्टी, वजन आधारित रॉयल्टी। हमारे यहां कोयला निकलता था। एक मन कोयले पर अगर हमें पांच रुपये मिल रहे थे और कोयले का दाम सौ रुपये था और अगर कोयले का दाम पांच सौ रुपये मन हो गया, तो भी हमको पांच रुपये रॉयल्टी मिली, चूंकि वह वजन आधारित था।

**उपसभाध्यक्ष** (**श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला**)**:** प्लीज़, आप अब कन्क्लूड करिए।

**डा. भीम सिंह**: अगर वह मूल्य आधारित होता, तो हमारी आमदनी बढ़ती, लेकिन यह सब नहीं हुआ और बिहार की उपेक्षा हुई। इसलिए बिहार को विशेष सहायता की जरूरत थी। हम प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय दिया है और बिहार को कुछ विशेष सहायता करने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम बजट का समर्थन करते हैं और अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA): Thank you. Shri A. A. Rahim; five minutes.

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Thank you, Sir, for this opportunity. Sir, before starting my speech I would pay homage to the people who lost their lives in the Wayanad disaster.

Sir, I speak here today on behalf of the millions of youth in our country who are struggling with unemployment and under-employment. Living in India today is extremely challenging. According to the data of Centre for Monitoring Indian Economy, the country's unemployment rate rose to 9.2 per cent in June. Food inflation increased from 6.6 per cent in 2022-23 to 7.5 per cent in 2023-24. The prices of gas, daily necessities, mobile tariffs, etc., have increased. The cost of living is skyrocketing every day, but incomes are declining. This is the situation. People are breathing heavily for their daily livelihood. I would like to speak about unemployment and under-employment in the country. I would like to share my concerns and disagreement with this Government's policy in this regard. The Government has a policy to dismantle the concept of permanent employment and replace it with contractual employment. They are promoting outsourcing; they are promoting privatisation of the public sector. According to the figures provided by the Union Minister, Dr. Jitendra Singh in Lok Sabha, there are 9,79,327 vacancies in various institutions and agencies of the Central Government. Furthermore, according to the latest data provided by the Railway Minister, 3.12 lakh posts are lying vacant in the Indian Railways. Moreover, we know about the Agnipath Scheme. Through this scheme, even the Union Government is trying to contractualise the recruitment of the Indian Army. This Government is quietly carrying out the process of elimination. By eliminating permanent posts, they are undermining the reservation policy. This action has severely marginalised the OBCs and SC/ST communities by excluding them from the Government jobs and excluding them from the mainstream of the society. We need permanent jobs, neither internship nor incentives. Internship or incentive is not a remedy. The Government should immediately fill all vacant posts in the public sector and stop contractualisation. Exploitation by private institutions must end and the

workers should be guaranteed with appropriate wages and job stability. According to the Economic Survey, 5.4 million contract workers in India are employed through organised staffing companies. About 21.8 per cent of the total workforce is casual labours. Their condition is very poor. Highly educated youth are forced to work for low wages without job stability, healthcare or other benefits. There is no healthcare; there is no benefit and there is no social security. In short, this is a kind of modern slavery. The Union Government projected the Production-linked Incentive Scheme as Alladin's miracle lamp to do away with unemployment. Now, the Government has introduced a new miracle lamp titled Employment-linked Incentive Scheme. Incentive or internship is the remedy provided by the hon. Finance Minister. I would like to add one more thing. ... (*Time-Bell rings*) ... Rule 2(1)(d) of the Companies (CSR Policy) Rules, 2014 defines CSR and excludes the activities undertaken in pursuance of the normal course of business of the company as eligible CSR activity.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*.)

This is the Rule. Then how can the Government implement such a scheme like internship scheme? Through this scheme, the Government suggests CSR funds to be mobilised for this purpose. ...(*Time-Bell rings*.)... This is against the spirit of CSR. This is not the Union Budget. This is the Budget for only two States. Double engine is the *mantra* that Modi Government always chants. Now, it has become a double-engine *sarkar*. One engine is TDP and another engine is JD(U). Without the help of these two engines, the Government can't move a single step. That is why they are trying to fuel those engines. On behalf of Kerala, I would like to share my concerns and dissent over this Budget. We have been completely neglected. On behalf of the people of Kerala, I remind you that we will survive these undeclared economic sanctions. Thank you.

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; रसायन और उर्वरक मंत्री; तथा सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा)**: माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से अपने इस 2024-25 के बजट के समर्थन के लिए और बजट के प्रमुख बिन्दुओं के ऊपर प्रकाश डालने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले..

**श्री सभापति**: सर, आपके तो नाम में ही 'प्रकाश' है।

**श्री जगत प्रकाश नड्डा**: धन्यवाद, सर। उसमें भी 'जगत' जुड़ा हुआ है।

**श्री सभापति**: हाँ, 'जगत' जुड़ा हुआ है। 'जगत' में भी 'जग' कॉमन है। 'जग' मेरे नाम में भी है और 'जग' आपके नाम में भी है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री जगत प्रकाश नड्डा**: माननीय सभापति जी, जब मैं इस बजट की चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधान मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार में आने पर प्रधान मंत्री जी कोई भी बधाई देता हूँ और इस सदन के माध्यम से भारत की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, जब हम बधाई देते हैं, तो हमको यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कई बार लोग गलत तरीके से नैरेटिव रखने का प्रयास करते हैं। जब मैं लगातार तीसरी बार कह रहा हूँ, तो लगातार तीसरी बार 60 वर्षों के बाद कोई प्रधान मंत्री लगातार तीसरी बार चुना गया हो और उनको जनता का समर्थन मिला हो। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 60 साल पहले जब नेहरू जी ने तीसरी बार पद संभाला था, तो उस वक्त आज़ादी का एक euphoria था, कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान किया था और विपक्ष भी बिखरा हुआ था और विपक्ष भी कमजोर था, छोटी-छोटी पार्टियाँ विपरीत दिशा में चर्चा करके उभर रही थीं। लेकिन यह जो 2024 का चुनाव हुआ, यह चुनाव तब हुआ, जब विपक्ष भी मजबूत था और राजनीतिक दृष्टि से सभी लोग सक्षम रहे, ऐसे में प्रधान मंत्री मोदी जी को लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने का सौभाग्य भारत की जनता ने दिया। ...(**व्यवधान**)... भारत की जनता ने mandate दिया। यह mandate, stability का mandate है; यह mandate, continuity का mandate है; यह mandate, good governance का mandate है और यह mandate, unfoldment of *Viksit Bharat* का mandate है।

महोदय, मैं आज क्योंकि जयराम जी ने कुछ प्रश्न उठाने शुरू किये, इसलिए मैं इस पर और आगे नहीं जाता, नहीं तो अगर मैं statistics में जाऊँगा, तो मैं बता पाऊँगा कि कुछ लोग तीसरी बार लगातार कोशिश करने के बावजूद भी 100 का अंक नहीं ला पाए और सारी पार्टियाँ मिला लें तब भी कुल मिला करके हमारी भारतीय जनता पार्टी से भी पीछे रहीं। 13 राज्यों में ज़ीरो आया। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 64 में से 2 सीटें और 62 में बीजेपी आई। मैं अगर आंकड़े बताने लगूँ, तो बहुत से आंकड़े बता सकता हूँ, लेकिन for stability, for continuity, for unfoldment of *Viksit Bharat*, and for good governance and pro-poor policies के कारण यह mandate हमें दिया गया है। सभापति जी, यह जो बजट है, यह बजट inclusive growth का बजट है; यह बजट sustainable development का बजट है और यह बजट- ध्यान से सुनें - economic resilience का बजट है।

3.00 **P.M.**

आज दुनिया की सारी आर्थिक शक्तियाँ डगमगा रही हैं, दुनिया की सारी विकसित देश की आर्थिक स्थितियाँ डोल-मोल हो रही हैं, लेकिन हम economic resilience के साथ Covid-19 pandemic के बाद भी अगर खड़े हैं, तो यह हमारी economic resilience के बारे में बताता है। This Budget is a visionary Budget. यह हमारी दोनों आकाक्षाओं को पूरा करता है - एक तो

यह हमारी immediate needs को एड्रेस करता है और दूसरा, robust framework के तहत long-term prosperity की चर्चा करते हुए उसको आगे बढ़ाता है, यानी दूरंदेशी भी है और वर्तमान की परिस्थितियों में उन चैलेजेज़ को एक्सेप्ट करने वाला और उसको एड्रेस करने वाला बजट है। इसलिए मैं कहूँगा कि यह 360-degree impactful Budget है। यह बजट comprehensive है और economic social development को समर्पित है। इस बजट की priority क्या है? इस बजट की priority है infrastructure development, infrastructure logistics को मजबूत करना, उसकी नींव रखना, technological innovations, social welfare और उसके साथ-साथ विकसित तथा सबके लिए समान अवसर देना। हमें इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। यह forward-looking Budget है। यह आगे देखने वाला बजट है। इसमें policies को accelerate किया गया है, जो ग्रोथ को बढ़ा सके। यह जॉब्स को क्रिएट करने वाला बजट है। यह हमारे भारत को global start-up hub की तरह enhance करता है, इसलिए यह उसको भी बढ़ाने वाला बजट है। इस तरह से यह बजट सभी तरीके से सर्वसमावेशी है और ग्रोथ में inclusive है तथा सबकी चिंता करने वाला है।

मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि जब हम बजट पर चर्चा करते हैं, तो विद्वानों की तरह बड़े-बड़े technological terminology का उपयोग करते हैं कि यह ऊपर बढ़ गया, यह नीचे घट गया, यह दायाँ चला गया, यह बायाँ चला गया। बजट मतलब यह साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, यानी कोई intellectual हो, कोई economist हो, वह चार terminology बोले कि इसका रेट इतना है, इसका इतना परसेंट है और उसको जो समझने वाला हो, वही बजट का ज्ञाता होता है। लेकिन मैं साधारण भाषा में बजट को बताना चाहता हूँ। मैं कई बार इस विषय को बोल चुका हूँ। बजट चाहे देश का हो, चाहे किसी प्रदेश का हो, चाहे किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, चाहे किसी संस्था का हो और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चाहे किसी परिवार का हो, बजट तीन बातों पर निर्भर करता है - आमदनी, आमदनी की ताकत खर्च को तय करती है और कहीं घर में, कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कहीं प्रदेश में, कहीं देश में लिकेज तो नहीं है, छेद तो नहीं है, कहीं आमदनी और खर्च के बीच में हमारा जो धन है, उसमें कोई लिकेज तो नहीं है - इन तीन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए जिसको परिवार का बजट समझ में आता है, उसी भाषा में देश का बजट भी हमें समझना चाहिए। मैं इसके बारे में आगे और बताना चाहता हूँ कि size of the income, यानी आपके इनकम का साइज क्या है। कहने का मतलब यह है कि जब आपकी आमदनी कम होती है, तो आप साईकिल खरीदते हैं, आमदनी बढ़ती है, तो मोटर साईकिल खरीदते हैं, और आमदनी बढ़ती है, तो गाड़ी खरीदते हैं, फिर लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं। यह किस पर डिपेंड कर रहा है। यह आमदनी पर डिपेंड करता है। इसी तरह से आपकी quality of life भी इसी बात से तय होती है और देश की भी quality of life इसी बात से तय होती है। Larger the size of the economy, the larger will be the benefit to the people and larger will be the capacity to spend. इस बात का डायरेक्ट रिश्ता होता है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, खर्च की priority होनी चाहिए। खर्च किस पर हो रहा है। घर पर हम खर्च किस पर करते हैं, जो सबसे कमजोर होता है। घर पर हम खर्च किस पर करते हैं, essential चीजों पर खर्च करते हैं। जब ज्यादा पैसा आता है, तो हम extravagant हो जाते हैं, हम कंफर्ट्स पर चले जाते हैं। जब उससे ज्यादा पैसा आ जाता है, हम

luxury पर चले जाते हैं, लेकिन हमको खर्च की प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है और उस प्रायोरिटी को तय करना भी resilience of economy की बहुत बड़ी शर्त है। इसीलिए, मैं कहूंगा कि leakage-proof और last mile delivery assurance, ये बहुत जरूरी हैं। मैं "कांग्रेस" शब्द नहीं लूंगा, लेकिन लंबे समय तक जो लोग देश पर राज करते रहे, उन्होंने इन बातों पर कारगर कदम नहीं उठाये और ठोस कदम नहीं उठाये, जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे। इस कारण से आमदनी और लीकेज का बहुत गहरा रिश्ता रहा। एक समय में एक प्रधान मंत्री ने कहा कि मैं एक रुपया भेजता हूँ, 85 पैसे बीच में ही खर्च हो जाते हैं, 15 पैसे ही पहुंचते हैं। अब उसके बाद आप बजट की जितनी बात कर लो, वह देश के कितने हित का था, वह हमको समझ में आ जाता है। आंकड़ों से देश नहीं चलता है, उसकी leakage-proof व्यवस्था के साथ last mile delivery is important. इसीलिए मैं यह कहूंगा कि आज प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में direct benefit transfer के माध्यम से डिजिटल इंडिया बनाने का काम किया गया। इस कारण आज 37 लाख करोड़ रुपये भारत के आम नागरिकों के खातों में डालने का काम प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरीके से, लीकेज पर रोक लगने के कारण फाइव करोड़ fake ration cards समाप्त हुए। फाइव करोड़! कैसे चलता होगा देश? यह बजट से जुड़ा हुआ विषय है। 4 crore fake beneficiaries of LPG subsidies थी, वह बंद हुई। MNREGA में 7 लाख bogus नाम थे। 7 लाख! संख्या जोड़िए। कहां बढ़ता देश, कहां जाता देश, कैसे बढ़ता देश, चाहे कितना भी कमा लो! ...(**व्यवधान**)...

**श्री जयराम रमेश** (कर्नाटक): आप इस 7 करोड़ को ऑथेंटिकेट कीजिए।...(**व्यवधान**)...

**श्री जगत प्रकाश नड्डा:** जी हाँ, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। ...(**व्यवधान**)...

**MR. CHAIRMAN:** Jairam, again, you are sitting on your chair, interrupting and speaking without permission.

**श्री जगत प्रकाश नड्डा:** जयराम जी, मैं सब कुछ mygov से लेकर आया हूँ। ...(**व्यवधान**)... इसी तरीके से, लीकेज को रोकने के कारण गवर्नमेंट का टोटल 2.5 लाख करोड़ सेव होता है। इसी तरीके से, हम बहुत प्रयासपूर्वक मोदी जी के नेतृत्व में strict financial discipline लाकर informal economy को formal economy की तरफ ले गए। आपने सुना होगा, ये शब्द चलते थे कि कितना ऊपर से दोगे, कितना अंदर से दोगे? यह साधारण शब्दावली थी। कितना कैश में दोगे, कितना चेक में दोगे? यह साधारण शब्दावली थी। This was the order of the day. कितना underhand होगा, कितना overhand होगा? यह शब्दावली थी। आज यह बताते हुए मुझे खुशी है कि हमारी formal economy बढ़ी है। जब हम formal economy की बात करते हैं तो उसके कारण formal economy के structure में ज्यादा से ज्यादा लोग आए हैं।

आपने 1973 में बैंक्स को नेशनलाइज किया। मेरे आंकड़े सही नहीं हो सकते हैं, तब पौने तीन करोड़ से लेकर छः करोड़ के आसपास तक लोग account holders थे, लेकिन आज जन-धन योजना के तहत 50 करोड़ लोग बैंक account holders हैं और 50 करोड़ होने के बाद भी

उनको direct benefit transfer तो मिल ही रहा है, पांच करोड़ बहनों को कोविड में तीन महीने के लिए 500-500 रुपये उनके अकाउंट में सीधे मिले ही मिले, यह तो बेनिफिट हुआ ही हुआ, लेकिन हमारी formal economy का साइज भी बढ़ा। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आज उसके कारण आमदनी के स्रोत को देखें तो formal economy अग्रसर होने के तहत tax collection, जो 2014 में 6.3 लाख करोड़ था, वह आज 23.37 लाख करोड़ है। यह बढ़ी हुई economy है। 6 लाख करोड़ रुपये से 23 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। हमारा जीएसटी का कलेक्शन, जो 2017-18 में शुरू हुआ - हम चाहते थे कि उसे रात हमारे विपक्ष के लोग भी बैठते और प्रणब मुखर्जी जी के साथ वे भी बटन दबाते और जीएसटी का टैक्स शुरू होता, लेकिन नहीं हो पाया। उस समय जीएसटी का कलेक्शन 7.9 लाख करोड़ रुपये था, आज 20.18 लाख करोड़ रुपये है। इसी कारण से हमारा fiscal deficit आज 5.6 परसेंट पर आ गया है और जो Central Fiscal Deficit Target है, वह year ending 2025 तक projected है, 4.9 per cent of the GDP. इसलिए हम fiscal deficit को संभालते हुए इस बजट का 4.9 per cent fiscal deficit जाएगा और हम लोगों की सेवा की दृष्टि से आगे बढ़ने वाले हैं। महोदय, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है, big ticket programme, क्योंकि जब आमदनी बढ़ती है - और priority क्या होती है कि जो marginal section of the society है, उसकी मदद करना। महोदय, जब मैं big ticket programme का बात करता हूं, तो 'आयुष्मान भारत' - मुझे उस स्कीम से जुड़ने का सौभाग्य है। सभापति जी, मैंने पहले भा कहा था और आज फिर मैं आपके साथ और सदन के साथ शेयर करना चाहता हूं कि दुनिया में terminology चली थी - UHC, यानी जो UHC बोले, वह बड़ा progressive है। जब मैं वर्ष 2015 में World Health Assembly में गया, तो ऐसा लगा कि जैसे UHC पर चर्चा ना करें, तो वह देश किसी काम का नहीं। Universal Health Coverage_की बात होती है। हमें खुशी है कि 2017-18 में प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में Universal Health Coverage_का सबसे बड़ा world's largest health coverage programme 'आयुष्मान आरोग्य भारत' बना और 55 crore people, हमारी 12 crore families को 5 लाख रुपये का health cover सालाना देने का तय हुआ और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की गई। इससे फ़र्क क्या पड़ा, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, International Monetary Fund (IMF) बोल रहा है कि भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर निकल आए हैं। यह उसका फ़र्क पड़ा है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, International Monetary Fund (IMF) बोल रहा है कि India's extreme poverty has been reduced to less than one per cent. एक परसेंट से भी नीचे आ गया है। ये आंकड़े आते हैं।

'उज्ज्वला योजना' की बात करूं तो 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। World Health Organisation बोलता था कि लगभग 5 लाख महिलाएं, बहनें, जिनकी मृत्यु होती है, वह uncleaned cooking fuels के कारण होती है, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। आज health indicators बता रहे हैं कि pulmonary diseases कम हो रही है और महिलाओं में कम हो रही है। यह empowerment of women हुआ, और क्या है संख्या? वह 10 करोड़ है।

इसी तरीके से 'उजाला योजना' के तहत एलईडी बल्ब - कई बार लोग बोलते हैं कि मिडिल क्लास का क्या हुआ? 20,000 करोड़ रुपये के बिल में कमी आ गई। इसी तरीके से 47.78

mkw energy per annum बचाई गई। यह एलईडी बल्ब के बारे में है और एलईडी बल्ब कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, करीब 36 करोड़ बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं।

उसी तरीके से 'सौभाग्य योजना' है, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि 2 करोड़, 60 लाख घरों को नए बिजली के कनेक्शन दिए गए, उसमें 16,320 करोड़ रुपये खर्च हुए। सर, पैसा आया, कलेक्शन हुआ, गरीबों के लिए लगा, मार्जिनल सेक्शन ऑफ़ द सोसाइटी को लाभ मिला। हम 'प्रधानमंत्री आवास योजना' की बात पहले कर चुके हैं, उसके तहत 4 करोड़ घर बना चुके हैं। अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तय किया है, पहली कैबिनेट में फैसला लिया है कि 3 करोड़ घर और बनाएंगे और गरीबों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। तो 11 करोड़ टैप के कनेक्शन लगे और आईआईएम, बेंगलुरू का कहना है कि around two crore jobs will be generated. इसके ऑपरेशन की स्टेज पर 2 करोड़ जॉब्स सिर्फ जल-जीवन मिशन में ही क्रिएट होंगी, यह बात कही जाती है। Amount spent is Rs.2.68 lakh crore. उसी तरीके से किसान योजना, big ticket की बात करें, तो हमें याद है और उस समय कहा भी गया था agriculture debt waiver and debt relief scheme, यह 2008 में आई थी और उसका अमाउंट 52,000 करोड़ रुपये था।...(**व्यवधान**)... मैंने चैक किया। मैं पहले 72 ही बोल रहा था, लेकिन फिर मैंने चैक किया कि agriculture debt waiver and debt relief scheme के आगे 52,000 करोड़ लिखा है। ठीक है, 72 भी मान लेते हैं। मैं आपकी बात ही मान लेता हूं। हम 52,000 करोड़ रुपये देकर किसानों के चैम्पियन हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कुल मिलाकर 3 लाख 24 हजार करोड़ रुपये 17 installment में दो-दो हजार रुपये पहुंचाए गए and moreover that was a waiver and this is empowerment of farmers. यह हम empower कर रहे हैं, ताकि वे गरीब किसान हर फसल के पहले बीज खरीद सकें, हर फसल के पहले वह फर्टिलाइजर खरीद सकें, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और यह continuous process है और 3 लाख 24 हजार करोड़ रुपये हम लोगों ने खर्च किए हैं। जब मैं आगे अगला भाषण कभी दूंगा, तो वह 4 लाख करोड़ के आस-पास पहुंचा हुआ होगा। क्योंकि हर तीन महीने पर 20,000 करोड़ रुपये जुड़ने वाले हैं और यह continuous process चलने वाला है। उसी तरीके से कोविड के रिलीफ पैकेज में 20 लाख करोड़ रुपये दिए थे। मुझे याद है, जब कोविड के पैकेज की बात आई थी, तो विपक्ष ने हमारे ऊपर टिका-टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ इनको महीने का दे देते, कुछ इनको इस तरीके से दे देते। प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा था - We will convert a pandemic into an opportunity. हम आपदा को अवसर में बदलेंगे। जब वे 20 लाख करोड़ रुपये दिए गए, तो वे empowerment के लिए दिए गए, empowerment of farmers, FPOs के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए गए, empowerment of MSME sector के लिए काम किया गया और उस समय हमें कहा गया था कि this is a financial hoax. मैं यह बताना चाहता हूं कि आज कोविड के बाद दुनिया के विकसित देशों की इकोनॉमिज़ डगमगा रही हैं और हम bright spot की तरह चमक रहे हैं, उसका कारण है कि उस समय के पैकेज ने हमारे empowerment को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए big ticket programmes, formalization of economy और leakage proof, इन तीनों ने हमें empower किया है। हमने सबके साथ जस्टिस करने का प्रयास किया है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं यहां जब बजट पर चर्चा कर रहा हूं, तो मैं न्याय नहीं

कर पाऊंगा, जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, अगर सिर्फ निर्मला सीतारमण जी के 23 जुलाई के भाषण के बारे में चर्चा करूं। 23 जुलाई उसका एक पार्ट है। एक पार्ट उसका 2024 का 1 फरवरी है, जब इंटरिम बजट पेश हुआ था। इन दोनों को मिलाकर देखेंगे, क्योंकि पांच महीने का बजट हम पास कर चुके थे और अब यह अगले छह-सात महीने का बजट है, जिसको हम आगे लेकर आ रहे हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं, तो न्याय करने के लिए मैं कहता हूं कि यह mandate continuity के लिए है, stability के लिए है। दस साल पहले से जो कार्यक्रम चलाए गए, उसकी stability और continuity में यह 2024-25 का बजट है, उसको भी हमें समझ लेना चाहिए। इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा फोकस 'GYAN' पर रहा। GYAN -- G is for Garibi, Y is for Youth, A is for Annadata and N is for Nari Shakti. इन चार पिलर्स पर हम लोगों ने अपने विकास की कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसलिए 2047 में, जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने nine-pronged strategy को डेवलेप किया है। जो nine-pronged strategy हैं - पहला, productivity and resilience in agriculture है, दूसरा, employment and skilling, तीसरा, inclusive human resource development and social justice है। यहां सोशल जस्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। Social justice; Promotin of manufacturing sector; Service sector to be infused; Urban development; Energy security; Development and focus on infrastructure; Innovation, research and development and; Next Generation reforms. इन 9 बातों को ध्यान में रख करके, इस बजट को continuity में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। अगर हम उसकी बात करें, तो हम लोगों ने February – March में roof top solarisation की बात कही थी और इसमें लगभग 1 crore households को जोड़ने की बात कही थी। उसमें capital expenditure और infrastructure पर बहुत ही शुभ नम्बर निकाला था, 11 लाख 1,100 करोड़ रुपये जो कि 3.4 per cent of the GDP का infrastructure के लिए होगा।

सर, हम employment generation को boost करेंगे, Eastern region पर भी concentrate करेंगे। इसी दृष्टि से हमारे सारे कार्यक्रम चले हैं। हम MSME की बात करें, तो adequate finances उसमें प्रोवाइड किया गया। हमारी तरफ से relevant technologies को बढ़ाया जा रहा है, appropriate training दी जा रही है। इसी के साथ-साथ, इसी बजट में हम लोगों ने कहा था कि आयुष्मान भारत में हम आशा workers को भी जोड़ लेंगे और आंगनबाड़ी workers और helpers को भी जोड़ लेंगे। ये सारी चीजें in continuity में थीं। तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी हम लोगों का संकल्प था, उसको भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। Metro Rail और Namo Rail को भी हम आगे बढ़ाएंगे, इन बातों को हमने कहा है। हम लोगों ने Interim Budget में ही कहा था और उसी के continuation में सूर्य घर बिजली योजना में 1.2 करोड़ registrations हो चुके हैं और 14 लाख applications को हम लोगों ने scrutiny करके आगे बढ़ाया है। इस काम को 3 करोड़ तक करने का हमारा निश्चय है। इसी तरीके से "प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना" है। मैं बार-बार उस समय भी कहता था और आज भी कहता हूं कि हमें समझना होगा कि policy-making में Budget बहुत important है। मैं एक example से आपको बताता हूं। जब 1993 में मैं विधायक बना, तो उस समय PWD के बजट में – उस समय मेरी कांस्टेट्युअंसी में 85 परसेंट गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं थे। उस समय बजट की व्यवस्था यह थी कि PWD के पास

बजट आता था, वह किसी heads के तहत subdivide हो जाता था। Executive Engineer हमारे पास आते थे और वे हमसे कहते थे कि अपनी priority बता दो, हम उन priorities पर खर्च करेंगे। उस समय Budget करीब 40 लाख रुपये का होता था, हम बहुत हल्ला कर लें, तो 80 लाख रुपये तक पहुंचता था। अगर हमारी 80 सड़कें हैं, तो 1-1 लाख सबमें बंट जाता था। अब आप सोचिए कि पहाड़ में 1 लाख में सड़क क्या बनेगी, कितनी बनेगी। जब हम Executive Engineer से पूछते थे, तो वह हमसे बोलता था कि आप इसको concentrate करके 2-3 सड़कों पर लगा दो, तो 20 लाख, 30 लाख देने पर कहीं सड़क एक किलोमीटर बन गई, कहीं दो किलोमीटर बन गई। This was the speed. अब 2014 के बाद स्पीड और scale की बात करते हैं और उसके पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की करते हैं, तो पहली बार "प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना" आई और foolproof scheme आई। इस scheme के तहत रोड from the starting point to the end point एक साथ, इसकी बजटिंग की गई, in one go और हर constituency में लगभग 10-10, 20-20, all weather roads की budgeting हुई। आपको जानकर खुशी होगी की पांच साल के अंदर "प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना" के आने के बाद हमारे यहां, हमारी constituency में सिर्फ 5 per cent गांव सड़क से छूट गए और 95 per cent गांव सड़क से जुड़ गए। यह फर्क दिखाई देता है। जब मैं आपके सामने इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं और "प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना" के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि "प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना" में 25,000 habitations को जोड़ने का प्रावधान इस साल बजट में किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि PMGSY में 1,56,000 गांव all weather roads से जोड़ दिये गये हैं, यह बदलता भारत है। इसको भी हमको समझना चाहिए। इसी तरह से पूर्वी रीजन में, Eastern region में, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और MSME sector को special attention दिया गया है। सर, promotion के लिए Credit Guarantee Scheme को आगे बढ़ाया गया है, MSME के लिए new assessment model बनाया गया है, credit support के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, ताकि stress period में हम उन्हें support कर सकें और structural reforms की तरफ ध्यान दिया गया है, इसको आगे बढ़ाया गया है।

महोदय, जब हम key highlights की बात करेंगे, तो the first initiative will be to eradicate poverty, empower the poor और empower the farmers and also provide them logistic supports और provide logistic and strengthening of the Indian villages. हमारे भारत के गाँवों को भी strengthen करने के लिए और logistic support देने की बात भी इसमें कही गई है। महोदय, इसमें job creation पर फोकस है। Employment-Linked Incentive Scheme will create crores of new jobs across the country. इसके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। Focus on skill development पर जोर दिया गया है, boost on agricultural productivity पर जोर दिया गया है, manufacturing sector को सपोर्ट करने की बात भी इस बजट में कही गई है। Service sector is to be boosted. उसी तरीके से digital public infrastructure की application को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। महोदय, इन सभी चीजों को बजट के मूल प्रावधानों में रखा गया है।

महोदय, अब मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूं - क्योंकि मैं स्वयं अपनी पीठ थपथपाऊँ, यह उचित बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे लिए दुनिया कुछ बोलती है, तो हमें उसको समझना चाहिए। महोदय, जब मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, तो Economic Survey of India कह रहा है कि there are comfortable foreign exchange reserves and there is a stable exchange rate. वे ऐसा कह रहे हैं। उसी तरीके से IMF कह रहा है - 'India is now from fragile economy to a bright spot.' यह हम नहीं कह रहे हैं। अगर हम लोग आपस में बोलते रहें, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, दुनिया क्या बोलती है, वह महत्वपूर्ण है।

महोदय, IMF हमसे कैसे बोलता है? जब हम IMF में जाते हैं, तो हमसे चार बातें पूछकर बोलता है, You have done this. Very good. Very good. Very good. How have you done? Please demonstrate. Please tell us. आज यह स्थिति हो गई है। लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब IMF हमें ऐसे बिठाता था कि हाँ, Yes, what do you have to say? What projects you have brought? Let us see. We will examine and let you know. भारत को देखने का तरीका बदल गया है। आज वे हमसे पूछ रहे हैं कि तुम यह परिवर्तन कैसे लाए? यह परिवर्तन कैसे आया, क्यों आया - आज यह बोलते हैं। लेकिन पहले एक समय ऐसा भी था कि जब हमें कुरसी पर बिठाकर बोलते थे कि, अच्छा, तुम्हारी demand क्या है, हम study करके बताएंगे, लेकिन वे आज हमसे पूछ रहे हैं।

महोदय, अब सभी लोगों ने कहा है कि हम fifth largest economy में पहुँच गए हैं। क्या यह छोटी घटना है? हम 11वें नंबर पर खड़े थे। महोदय, पिछले दस सालों में, यानी, 2002-03 से लेकर 2014 में हम दो नंबर खिसके, और अब 11वें नंबर से छलांग लगाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। महोदय, हमने किसको पछाड़ा है? हमने ब्रिटेन को पछाड़ा है, जिसने हम पर 200 साल राज किया। हम उसको पछाड़कर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। पर हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तक जाना है और वहाँ आप सबके सहयोग से जाना है और हमें आपका भी सहयोग मिलेगा - इस बात का मुझे विश्वास है।

महोदय, Morgan Stanley क्या बोलते हैं? वे बोलते हैं - 'India is different from 2013.' Moody's क्या कहते हैं? वे कहते हैं - 'GDP growth forecast increase is projected for the year 2024 at the rate of 8 per cent.' Regarding growth rate, IMF Economic Outlook Growth Projections क्या बोलता है? मैंने यह पिछली बार भी बताया था। मैं इसको बार-बार इसलिए बताना चाहता हूं, क्योंकि Economy should always be comparison के टर्म्स में देखनी चाहिए, हमें compare करना चाहिए। आज यूएसए का ग्रोथ रेट 2.7 परसेंट projected है, जर्मनी का 0.2 परसेंट है, फ्रांस का 0.7 परसेंट है, जापान का 0.9 परसेंट, यू.के. का 0.5 परसेंट है। मैंने ये सारे वे नाम लिए है, जो विकसित देश हैं। महोदय, इंडिया का ग्रोथ रेट 6.8 परसेंट है। यह हमारा ग्रोथ रेट है और हम वर्ल्ड की economy में 15 परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी Services Purchasing Managers' Index, that has risen to 61.1 points और Manufacturing Purchasing Managers' Index में इंक्रीज़ होकर 58.5 points पहुँच गई हैं। महोदय, आज हमारा Net Financial Wealth Percentage GDP का 97 per cent पहुँच गया है और हमारी electronics manufacturing 6 गुना बढ़ी है। हमारे इलेक्ट्रोनिक्स एक्सपोर्ट्स 75,000 करोड़ रुपये के बढ़े हैं। इसी तरीके से, हम मोबाइल की बात करते हैं। At one point of time, 92 per

cent of the mobiles were imported. Now, 97 per cent of the mobiles are being manufactured here in India. स्टील में हम नंबर चार से नंबर दो पर आ गए हैं। हम थर्ड लारजेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट, जिसके बारे में राधा मोहन अग्रवाल जी ने भी उस दिन चर्चा की, मैं बताना चाहता हूँ। हमने ऑटोमोबाइल्स में खरीदी बढ़ाई है। हम तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इसका मतलब जेब में पैसा आया है, तब खरीदा है। ऐसे ही तो नहीं खरीद लिया। अगर इकोनॉमी में पैसा नहीं हो, तो कौन गाड़ी खरीदेगा। यह भी स्पष्ट बताता है कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको किया है। यह सब इसलिए पॉसिबल हुआ है, क्योंकि प्रो-पीपल प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने का काम किया है। मेट्रो रेल की बात करें, तो हम पाँच शहरों से बढ़कर 20 शहरों में पहुंच गए हैं। हम अगर एयरपोर्ट्स की बात करें, तो 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे और आज 149 एयरपोर्ट्स बनकर तैयार हो गए हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री पहले भी था, आज भी हूँ। मैं स्वास्थ्य की बात जरूर करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 387 मेडिकल कॉलेजेज़ थे, I am proud to declare that now we have got 706 medical colleges. The undergraduate seats were 51348 and now, the undergraduate seats are 1,08,940. आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 16 से 23 पहुंच गई है। आईआईएमस आज 20 हो गए हैं। आईआईआईटीज़ 2014 में नौ थे, आज वे 25 हो गए हैं। उसी तरीके से, जो नेशनल हाईवेज़ 12 किलोमीटर प्रतिदिन बना करते थे, आज 28 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे हैं। यह हमारी सरकार ने किया है। इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क 60,800 किलोमीटर पूरा हुआ है। यह सब कुछ हुआ है, जिसमें पैसा भी लगा है, लेकिन उससे ज्यादा प्रधान मंत्री, मोदी जी की इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति लगी है, जिसके कारण ये आकांक्षाएं पूरी हुई हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि देश एक समय में एक अवस्था से गुजर रहा था कि सब कुछ ऐसे ही चलेगा, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, यह ऐसे ही रहने वाला है। आज साधारण मानवी भी कहता है कि भारत आगे बढ़ा है, बदला है, बदलेगा, आगे चलेगा और प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में चलेगा, यह बात निकलकर आई है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन रिफॉर्म्स का समय 2004 से 2014 तक था, लेकिन शायद वह डिकेड, वह दशक व्यर्थ चला गया। हमने उसका उपयोग नहीं किया। सर, कई बातें है। जैसे आज यह बजट के ही सिलसिले में आप बताइए कि आपने कहा कि नहीं कहा कि गाँव का व्यक्ति तो डिजिटल जानता ही नहीं है? गाँव में यह वाईफाई लाकर क्या करोगे? कहा था या नहीं कहा था? यह डिजिटल इंडिया, यह डिजिटाइजेशन क्या है। यह भारत तो पढ़ा-लिखा नहीं है! मैं बताना चाहता हूँ कि आज हाट में बैठने वाला सब्जी वाला भी क्यूआर कोड लेकर डिजिटल इंडिया में पेमंट लेता है।

MR. CHAIRMAN: He has to yield. *...(Interruptions)...* He does not yield. *...(Interruptions)...*

**श्री जगत प्रकाश नड्डा**: मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉमन सर्विस सेंटर लाखों के हिसाब से गाँव में... ...(**व्यवधान**)... राजीव जी, बैठ जाइए। गाँव में लाखों के हिसाब से कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं। लाखों मतलब दो लाख, डेढ़ लाख से ऊपर कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं और वहाँ यूथ उस कॉमन सर्विस सेंटर में बैठकर ऑनलाइन कर रहा है। आज गाँव में बैठा हुआ किसान अपनी ई-नाम की मंडी से जुड़कर वह दुनिया के और देश के... आप किसानों की बात करते हैं और स्कीम

की बात करते हैं। आप किसानों की डिमांड्स की बात करते हैं। आज किसान कहाँ पहुंच गया है, आप कहाँ उसे पीछे बैक गियर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। किसान की उपज का मार्केट रेट दुनिया में और देश में कहाँ कितना है, वह किसान तो यह जानने का हकदार हो गया है, यह परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि ये जो एनुअल इनफ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं, इसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि 2004 से 2014 तक एनुअल इनफ्लेशन रेट 8.02 परसेंट था। 2013-14 की शुरुआत में वह double digit में पहुंच गया था। इसके साथ-साथ आज मैं कह सकता हूं कि हमारा जो inflation रेट है, वह 3.3 per cent पहुंच गया है। यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 2004 में Non-Performing Assets (NPAs) 7.8 per cent था और 2013 में 12.3 per cent तक पहुंच गया। यूपीए के टाइम में External Commercial Borrowings (ECBs) की Compounded Annual Growth Rate 21.1 per cent थी। आज NDA में वह annual 4.5 per cent पहुंच गया है। उसको कंट्रोल किया गया है। Capital Expenditure during NDA regime, वाजपेयी जी के टाइम में 31 per cent था और बाद में यूपीए के टाइम में reduce हो कर 16 per cent हो गया और आज मोदी की गवर्नमेंट में वह 28 per cent पर आ गया है। Angle Tax किस सरकार के टाइम पर आया था और किसने उसको हटाया, ये सब बातें हमारे ध्यान में हैं। यह भी हमें समझ में आना चाहिए।

मैं यहां एक बात जरूर कहूंगा, Twitter पर मैंने देखा, कई बालक बुद्धि पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने Twitter पर एक ही ट्वीट पर देखा - यह उद्योगपतियों का बजट है, एक कांग्रेस का manifesto है, यह copy-paste है और यह बजट खराब है। आप बोलना क्या चाहते हो, भाई! ...(**व्यवधान**)... आप बोलना क्या चाहते हो, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। उद्योगपतियों का बजट है, copy-paste है, तो उद्योगपतियों का क्या आपने पेस्ट किया? फिर कहा कि खराब है, तो क्या यह आपका खराब है? आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। ...(**व्यवधान**)... देखिए, अमृतकाल में interim Budget क्या है? Economic policies that sustain growth, facilitate inclusive development and create opportunities for all. मैंने पहले भी कहा है कि यह next generation reforms है और MSME sector को बढ़ाने वाला है।

अभी बजट पर चर्चा चल रही है और बजट पर कुछ लोग राजनीतिक बातें कर देते हैं और मैं एक पार्टी का अध्यक्ष भी हूं, सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हूं, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। आजकल कुछ लोग ओबीसी के चैम्पियन बन गए हैं। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अपने पास copyright मत रखो। आप ओबीसी के चैम्पियन कब से बन गए? मैंने पहले भी कहा था कि यह जो tutored statements होती हैं, जिनकी tutoring होती है, उनको tutoring पूरी करनी चाहिए, अगर आधी-अधूरी करते हैं, तो दिक्कत होती है। मैं पूछता हूं कि काका कालेलकर की रिपोर्ट किस समय में आई थी? मैं जानना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसके समय में आई थी, वह कहां पड़ी थी, केंद्र सरकार के किस cupboard में पड़ी थी, कहां उसको धूल लग रही थी और कहां उस पर चर्चा हुई थी? इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर 6th September को राजीव गांधी जी ने लोक सभा में क्या कहा था? Mandal Commission's Report is 'One man's obstinacy' और फिर आगे कहा, The Congress under the leadership of Indira Gandhiji, had raised the slogan "न जात पर न

पात पर"। आज आप वोटों की खातिर इतने लालायित हो गए हैं कि आज आप ओबीसी के चैम्पियन बनने लगे हैं। आप कांग्रेस पार्टी में हैं, मैं आपसे ऐसे ही पूछना चाहता हूं कि आपकी वर्किंग कमिटी में कितने ओबीसी हैं? आप बताइए कि आपके Rajiv Gandhi Foundation के Board में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं? ...(**व्यवधान**)... आप बताइए कि यूपीए के टाइम में जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी, उसमें कितने ओबीसी, कितने एससी और कितने एसटी थे? ...(**व्यवधान**)... यह जो नया प्रेम जगा है, अब वह मुहावरा है -घड़ियाली आँसू। अब मुहावरा क्या कहें, घड़ियाली आँसू बहाने से काम नहीं चलता है, ओबीसी के साथ जीना पड़ता है, यह दिखा कर काम नहीं चलता है। हम अगर प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में कहें, तो चाहे मोदी जी की पहली कैबिनेट थी, चाहे दूसरी कैबिनेट, चाहे तीसरी कैबिनेट, सबसे ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी रहे हैं, तो हमारी कैबिनेट में रहे हैं।

आजकल अग्निवीर पर अग्नि लगी हुई है। उसमें भी बहुत ज्यादा politics हो रही है। आप आर्मी के बहुत बड़े हिमायती हो गए। देखिए, मैं पहले कहता हूँ कि national interest के साथ politics नहीं होनी चाहिए। आप अग्निवीर की recommendations को ज़रा गहराई से पढ़िए, उसकी recommendations को देखिए, दुनिया की आर्मी को study कीजिए, देश की आर्मी को study कीजिए। जब attack होगा, तो वह यह नहीं पूछेगा कि यह कमल को जा रहा है या यह हाथ को जा रहा है, उसकी गोली उसी तरीके से चलेगी। इसीलिए हमको आर्मी को politics से बाहर रखना चाहिए। यह जो फैसला लिया गया है, 400-500 से ज्यादा मीटिंग्स और consultations के बाद लिया गया है, सिर्फ किसी की भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं, भारत की फौज को मुस्तैद करने के लिए, दुनिया की सबसे अच्छी फौज बनाने के लिए लिया गया है। लेकिन आज आप आर्मी के और अग्निवीर के चैंपियन बन गए और आप पेंशन की बात करने लगे। 1971-72 की One Rank One Pension में, 1971-72 से मुझे नहीं मालूम उसके बाद कांग्रेस की कितनी सरकारें आकर चली गईं, the number of Governments which must have come and have participated, आपने क्या किया! यह प्रधान मंत्री, मोदी जी ने तय किया - One Rank One Pension. और आपने क्या किया था? हमारे यहाँ उसको बोलते हैं पायता रखना, यानी शगुन रखना। चिदम्बरम साहब ने 2014 के बजट में जाते समय पायता रखा, शगुन रखा 500 करोड़ रुपए का कि we will look after the issue of One Rank One Pension. ये प्रधान मंत्री, मोदी जी हैं, जिन्होंने 1,15,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए। इसलिए अग्निवीरों की चिंता मत कीजिए, उनकी पूरी चिंता हो रही है और भारत की आर्मी पूरे अच्छे तरीके से आगे बढ़ कर आएगी, इस बात को भी हम कहते हैं।

अभी मैं यह भी बताना चाहता हूँ, मैं उसको authenticate कर दूँगा, शायद कागज रह गया, यह MSP के बारे में है। आजकल आप किसानों के बड़े चैंपियन बन गए हैं, MSP के बारे में बहुत आँसू बहा रहे हैं। मि. के.वी. थॉमस ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि MSP देना conducive नहीं है। यह आपने जवाब दिया है, यह आपका जवाब है। आज आप MSP के चैंपियन बन रहे हैं! मतलब क्या ऐसा है कि जब पाला बदल जाए, तो भाषा बदल जाती है? देशभक्ति तो बराबर की होनी चाहिए। लेकिन स्वामीनाथन कमीशन की recommendation में production cost plus 50 per cent margin, MSP में this was accepted by none other than Prime Minister, Narendra Modi. That you have to understand. हाँ, मैं बताना भूल गया, प्रकाश

जावडेकर जी के 2010 के क्वेश्चन के जवाब में मि. के.वी. थॉमस, Union Minister of State for Agriculture, उन्होंने कहा, "The recommendation, however, has not been accepted by the Government."

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please mention the date and time. कब कहा, यह बताइए।

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: In 2010, Bharatiya Janata Party MP, Shri Prakash Javdekar in Rajya Sabha had asked the UPA Government, if they had accepted the recommendations of the Swaminathan Commission regarding calculation of remunerative prices to be paid to the farmers in 2010. मैं exact date भी निकाल कर दे दूँगा। "The recommendation however has not been accepted by the Government because MSP is recommended by the Commission for agriculture cost and prices. Based on the objective criteria and considering variety of relevant factors, hence, prescribing an increase of at least 50 per cent of the cost may distort the market."A mechanical linkage between the MSP and the cost of production may be counterproductive in such cases. उस दिन जो आपको counterproductive दिखता था, आज आप उसके बड़े रहनुमा बन रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी ने यह पहले कर दिया है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मैं एक-दो विषय और भी आपके सामने रखते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा। पता नहीं क्या है, मुझे थोड़ा सा लगा कि इस हाउस में ज्ञान का वर्धन उस तरफ कुछ ज्यादा आ जाता है। जब उधर रहते हैं, तो उसकी छाया ज्यादा पड़ती है। उधर से दो महानुभावों ने भाषण दिये। एक भाषण पी. चिदंबरम साहब ने दिया और एक भाषण हमारे सिब्बल साहब ने दिया।

**श्री सभापति**: दोनों ही सीनियर एडवोकेट्स हैं।

**श्री जगत प्रकाश नड्डा**: हाँ, दोनों ही सीनियर एडवोकेट्स हैं और दोनों ने बजट पर ऐसा भाषण दिया, जैसे बजट के बारे में तो उनके दिमाग में क्या बढ़िया-बढ़िया आईडियाज़ हैं, परन्तु ये बढ़िया-बढ़िया आईडियाज़ यहाँ बैठ कर क्यों नहीं याद आये थे. जो वहाँ जाकर उनको याद आने लगे। एक ने तो एजुकेशन का रिफॉर्म ही रख दिया। यह अलग बात है कि एजुकेशन रिफॉर्म शायद 34 साल बाद, जब यहां मोदी जी की सरकार आई, तब एजुकेशन का रिफॉर्म आया, यह बात अलग है।

पी. चिदंबरम साहब ने कहा यह 500 कंपनियाँ ही क्यों, जो जॉब्स के लिए इंटर्नशिप देंगी, इसको बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं? वे इतने पढ़े-लिखे व्यक्ति, इतने जानकार व्यक्ति हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि वे कंपनियाँ सिलेक्ट की जाएँगी, जिनके पास इंटर्नशिप की, उसको ट्रेनिंग देने की कैपेसिटी होगी, जिनके पास ट्रेनिंग देने के लिए सीएसआर फंड्स होंगे। अगर इतनी

लॉजिक भी समझ में नहीं आती, इतनी भी बात समझ में नहीं आती, तो मुझे लगता है कि वहाँ रहने से ही ज्यादा ज्ञान वर्धन होता है, अगर वे वही रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदय, मुद्दे बहुत हैं। मेरे साथी और भी मुद्दे रखने वाले हैं, कल निर्मला जी पूरी बात को रखेंगी। मैं यही बताना चाहता हूँ कि यह बजट 10 साल की कंटिन्यूटी का बजट है और इस बजट में उस कंटिन्यूटी में एक लंबी छलांग है और यह छलांग इकोनॉमी को स्टेबिलिटी भी देती है, कंटिन्यूटी भी देती है और मजबूती के साथ 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब का प्रयास' - इस मंत्र को लेकर के सरकार चल रही है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

## STATEMENT BY MINISTER

### The Landslide incident in Wayanad District, Kerala

**श्री सभापति**: केन्दीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द राय। केरल के वायनाड जिले में दिनांक 30 जुलाई, 2024 को भू-स्खलन की घटना के संबंध में सदन में एक वक्तव्य देंगे। माननीय मंत्री जी।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय)**: महोदय, केरल राज्य के वायनाड जिले में आज सुबह के शुरुआती घंटों में भू-स्खलन ...(**व्यवधान**)...

**एक माननीय सदस्य**: सर, स्टेटमेंट की कॉपी नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री नित्यानन्द राय**: महोदय, केरल राज्य के वायनाड जिले में आज सुबह के शुरुआती घंटों में भू-स्खलन की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ...(**व्यवधान**)... इसकी कॉपी मिल जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: First, listen to the Minister. Please, listen.

**श्री नित्यानन्द राय**: महोदय, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अब तक राहतकर्मियों द्वारा- महोदय, मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा कि चूंकि लोकसभा में अभी हमने मृतकों के संबंध में जो आंकड़े दिए हैं और अभी जो रिपोर्ट आई है, उसमें थोड़ा अंतर है। वहां हमने 49 का आंकड़ा दिया था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ 70 शवों को निकाल लिया गया है, यानी वहाँ 70 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग घायल हैं। अब तक दो व्यक्तियों को मलबे से जीवित बचाया गया है और लगभग 250 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने श्री जॉर्ज कुरियन, माननीय राज्य मंत्री को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए रवाना कर दिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने केरल के माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार के द्वारा हर